घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 267- मंगलवार 28- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा शुरू नहीं...विपक्ष का हंगामा,छात्रों की पिटाई मामले पर बहस के लिए अड़ा

पेपरलीक बिल पर चर्चा करने को विपक्ष तैयार,वोटिंग होगी

नई दिल्ली,27 जुलाई 2026। 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' को लेकर संसद में हंगामा खत्म होने की उम्मीद है। विपक्ष आज इस पर चर्चा शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने पार्टियों के नेताओं से बातचीत की। जिसके बाद सरकार और विपक्ष दोनों ही 28 जुलाई को बिल पर चर्चा करने और वोटिंग के लिए तैयार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंगलवार दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। इससे पहले सोमवार को लोक परीक्षा संशोधन बिल पेश किया गया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष छात्रों पर हृश्वश्वज्ञ पेपर लीक के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर बहस के लिए अड़ा रहा। कांग्रेस का कहना है कि इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर बयान दें। इस वजह से लोकसभा की कार्यवाही दिन में 4 बार स्थगित हुई। जब भी कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस, सपा के सांसद वेल में बैनर लेकर पहुंच जाते और नारेबाजी करने लगते।

खड़गे बोले...अमित शाह सदन में आकर बयान दें...

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, 'हम चर्चा से डरने वाले नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि अमित शाह को सदन में आना चाहिए और बताना चाहिए लाठीचार्ज क्यों करवाया।'

इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी सांसदों ने जिंदाबाद के नारे लगाए...

पिछले हफ्ते छात्रों के जोरदार प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को जब संसद भवन पहुंचे तो मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। उनके समर्थन में नारे में भी लगाए गए। बीजेपी सासंदों ने प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस्तीफे के बाद प्रधान पहली बार सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए। संसद के मकर द्वार पर ही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत विपक्ष के कई सांसद भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जंतर-मंतर पर सीजेपी की अगुवाई में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को हुई घटना के लिए केंद्रीय गृह मंत्री (अमित शाह) की जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान ने पिछले हफ्ते शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन खत्म कर लिया।

पेपर लीक बिल पर चर्चा न होने देना दुर्भाग्यपूर्ण : रिजिजू

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देशभर के छात्रों की मांगों और हाल में हुए छात्र आंदोलन को ध्यान में रखते हुए सरकार परीक्षा में पेपर लीक और अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए आज एक बेहद महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लेकर आई है। उन्होंने कहा कि यदि इतने बड़े छात्र आंदोलन के बाद भी इस मुद्दे पर संसद में चर्चा नहीं हो पाती, तो यह न संसद के लिए अच्छा है और न ही लोकतंत्र के लिए। ससंद बहस और चर्चा का सर्वोच्च मंच है, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर यहीं सार्थक चर्चा होनी चाहिए। रिजिजू ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में आरोप लगाया कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं तथा नारेबाजी, काले कार्ड दिखाकर और अन्य तरीकों से सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों से अपील की कि वे देश के छात्रों की भावनाओं को समझें और हंगामा करने के बजाय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए बड़ा निर्णय लिया है और इसके लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक विधेयक पेपर लीक रोकने के लिए सख्त और समयबद्ध प्रावधानों के साथ-साथ दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करता है, जिससे छात्रों का भविष्य अधिक सुरक्षित होगा।

विपक्ष के सांसदों ने सरकार पर लगाया आरोप,कहा...'सरकार जनता और छात्रों को कानून के नाम पर कर रही गुमराह'

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान सोमवार को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026, छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसदों ने सरकार पर छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करने,पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। वहीं, विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी और गृह मंत्री अमित शाह की निंदा की भी मांग दोहराई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में छात्रों के खिलाफ अब भी एफआईआर दर्ज की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस सूचना की अभी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि यदि इसकी पुष्टि ही नहीं हुई है, तो फिर इस पर बहस का क्या औचित्य है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सार्वजनिक परीक्षाओं संशोधन विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार पहले भी इस विषय पर कानून बना चुकी है। उन्होंने पूछा कि यदि पहले के कानून पर्याप्त थे, तो नए संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया और सवाल किया कि क्या सरकार को पढ़े-लिखे छात्रों से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा महसूस हो रहा था। यदि सरकार वास्तव में कार्रवाई करना चाहती, तो अब तक जांच एजेंसियां ठोस नतीजे सामने ला चुकी होतीं। इमरान मसूद ने पेपर लीक के मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया है और मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। उनके अनुसार सरकार केवल नए कानून लाने की बात कर रही है,जबकि प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि यदि समय पर कार्रवाई होती,तो उसके परिणाम भी दिखाई देते। लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान आरोप लगाया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक अदालत ने एक आरोपी को जांच में खामियों के कारण बरी कर दिया था।

अस्पताल से छुट्टी के बाद राजघाट पहुंचे सोनम वांगचुक,बोले...गांधीजी का रास्ता आज भी सबसे सही...

नई दिल्ली,27 जुलाई 2026। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद अपनी पत्नी गीतांजलि आंग्मो के साथ राजघाट पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 26 दिन के उपवास और आंदोलन खत्म होने के बाद उन्होंने सबसे पहले गांधीजी को नमन किया।

गांधीजी के रास्ते को बताया आज भी प्रासंगिक

राजघाट पर वांगचुक ने कहा कि वह सबसे पहले महात्मा गांधी को याद करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि गांधीजी का दिखाया शांति और अहिंसा का रास्ता आज भी उतना ही सही है, जितना सौ साल पहले था। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से वह लद्दाख में इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और अब उन्हें विश्वास हो गया है कि यह पूरे देश में भी कारगर है।

युवाओं और देशवासियों का जताया आभार

वांगचुक ने कहा कि इस आंदोलन की सफलता किसी ताकत या हिंसा से नहीं,बल्कि शांति और लोगों के सहयोग से मिली है। उन्होंने देश के युवाओं,आम नागरिकों और आंदोलन से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र की ताकत है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वांगचुक ने कहा कि यह केवल शुरुआत है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बातचीत के जरिए परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा और देश में अधिक पारदर्शी व्यवस्था बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों का सम्मान होना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर समाधान निकाला जाना चाहिए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वांगचुक अब लद्दाख के लिए रवाना होंगे।

आरबीआई लाएगा 10 और 20 रुपये के पॉलीमर नोट,सरकार ने ट्रायल को मंजूरी दी...

नई दिल्ली,27 जुलाई 2026। केंद्र सरकार ने 10 रुपये और 20 रुपये के पॉलीमर बैंकनोटों के फील्ड ट्रायल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा में लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि क्रक्चढ्ढ ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम के तहत केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। ट्रायल सफल रहने पर इन नोटों को नियमित रूप से जारी करने का भी प्रस्ताव है। सरकार के अनुसार, आरबीआई ने बताया है कि अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों में पाया गया है कि पॉलीमर बैंकनोट सामान्य कागजी नोटों की तुलना में अधिक समय तक चलते हैं। ये नोट ज्यादा टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते। हालांकि, यह प्रस्ताव अभी शुरुआती चरण में है। इसलिए इसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है और अंतिम फैसला ट्रायल के नतीजों के आधार पर लिया जाएगा, ताकि सभी जरूरी पहलुओं का सही आकलन हो सके। सरकार ने साफ किया है कि कागजी मुद्रा को पूरी तरह बंद करने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि पॉलीमर बैंकनोट कागजी नोटों के साथ ही चलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नकद और डिजिटल भुगतान दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और लोगों को भुगतान के अलग-अलग विकल्प उपलब्ध कराते हैं। इसलिए पॉलीमर नोट आने से डिजिटल भुगतान व्यवस्था पर तत्काल कोई असर नहीं पड़ेगा और दोनों व्यवस्थाएं साथ-साथ चलती रहेंगी।

'फिर धरने पर बैठेंगे', कॉकरोच जनता पार्टी की केंद्र सरकार को खुली चेतावनी

नई दिल्ली,27 जुलाई 2026। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्र सरकार को एक बार फिर खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई नहीं रोकी गई तो संगठन दोबारा देशव्यापी धरना-प्रदर्शन शुरू करने के लिए मजबूर होगा। पार्टी का आरोप है कि पहले हुए समझौते के बावजूद विभिन्न राज्यों में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर निगरानी रखी जा रही है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। सीजेपी का कहना है कि यह भारत सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन और आपसी सहमति का स्पष्ट उल्लंघन है।

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को टैग किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि संगठन लगातार यह देख रहा है कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई न करने को लेकर हुए समझौते का पालन नहीं किया जा रहा है। उनका दावा है कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में छात्रों और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है या गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी आंदोलन से जुड़े लोगों पर नजर रखी जा रही है और उन्हें अलग-अलग तरीकों से परेशान किया जा रहा है।

आशुतोष रांका ने विशेष रूप से दिल्ली की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराने वाले स्वयंसेवकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। उनके अनुसार ऐसे कई स्वयंसेवकों को हिरासत में लिए जाने की रिपोर्ट सामने आई है, जबकि उनका काम केवल प्रदर्शनकारियों को भोजन, पानी, आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है और यह पहले हुए समझौते का सीधा उल्लंघन है। सीजेपी प्रवक्ता ने सरकार से मांग की कि कानूनी मामलों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने से संबंधित लिखित समझौते की प्रति संगठन को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि यह दस्तावेज भारत सरकार द्वारा तय समयसीमा के अनुरूप साझा किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में किसी तरह का विवाद न रहे।

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की कानूनी लड़ाई लड़ेगी सीजेपी,कपिल सिब्बल ने एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की...

कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों में देशभर में कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर तक वकीलों का नेटवर्क बनाने की घोषणा की है। वहीं, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इस पहल के लिए एक करोड़ रुपये का योगदान देने की घोषणा की। सोमवार को यहां आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि पार्टी एक वेबसाइट तैयार करेगी, जिसके माध्यम से जनहित के मुद्दों पर काम करने के इच्छुक वकीलों को जिला स्तर पर जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के जरिए प्रदर्शनकारियों और युवाओं को देशभर में कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सिब्बल ने कहा कि सीजेपी एक ऐसा ढांचा तैयार करेगी, जिसके माध्यम से यह जानकारी एकत्र की जाएगी कि किस स्थान पर क्या घटनाएं हुईं, किन छात्रों या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें किस प्रकार की कानूनी सहायता की आवश्यकता है।

प्रदर्शनकारियों पर एके 47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी निलंबित

पटना,27 जुलाई 2026। बिहार बंद के दौरान 25 जुलाई को सिवान में हुए बवाल और पुलिस की ओर से एके-47 से फायरिंग के मामले में पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। फायरिंग करने वाले सिपाही अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। वहीं, कुछ पुलिसकर्मियों के बीच इस फैसले को लेकर नाराजगी की भी चर्चा है। जानकारी के अनुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर संबंधित सिपाही के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। मामले की विस्तृत जांच भी कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने घटना को गंभीर मानते हुए पहले ही संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की थी। गौरतलब है कि 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान सिवान में प्रदर्शन के बीच हालात तनावपूर्ण हो गए थे। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती नजर आई। इसी दौरान एक पुलिसकर्मी द्वारा अत्याधुनिक हथियार एके-47 से फायरिंग की गई।

डॉक्टर बनने का सपना टूटा,छात्रा ने की आत्महत्या,सुसाइड नोट में ये लिखा

अहिल्यानगर,27 जुलाई 2026। देश में नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में एक दुखद घटना सामने आई है। कर्जत तालुका के जलालपुर गांव की छात्रा अंकिता सुरेश सांगले ने आत्महत्या कर ली। परिवार के अनुसार, अंकिता ने नीट री-एग्जाम में कम अंक आने के सदमे में यह कदम उठाया। सुसाइड नोट में अंकिता ने लिखा कि उसे कम अंक मिलने से डॉक्टर बनने का सपना टूट गया है। नोट में उसने यह भी स्पष्ट किया कि उसके आत्महत्या के लिए उसके अभिभावकों को जिम्मेदार न ठहराया जाए। अभिभावकों ने बताया कि अंकिता को पहली बार नीट परीक्षा में अच्छे अंक आए थे लेकिन पेपर लीक की घटना के कारण री-एग्जाम कराना पड़ा। री-नीट में कम अंक मिलने के बाद वह लगातार तनाव में रहने लगी थी। परिवार का कहना है कि वह डॉक्टर बनने की बहुत उत्सुक थी और परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह लगी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही रिश्तेदार अंकिता के घर पहुंचने लगे हैं। आस-पास के लोग भी दुख व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पेपर लीक न हुआ होता और दोबारा परीक्षा में अंकिता को अच्छे अंक मिले होते तो आज वह हमारे बीच होती।

जंतर-मंतर लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सीजेपी बोले-प्रदर्शन का मतलब लाठीचार्ज नहीं

नई दिल्ली,27 जुलाई 2026। छात्र आंदोलन के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर पर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की घटना पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान पुलिसिया बल प्रयोग पर सख्त एतराज जताया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है और केवल प्रदर्शन होने के आधार पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग को जायज नहीं ठहराया जा सकता। शीर्ष अदालत ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जंतर-मंतर घटना और देश भर में छात्रों पर हुई कार्रवाई से जुड़ी सभी याचिकाओं पर आज विस्तृत सुनवाई करने का फैसला किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष पुलिस की बर्बरता का मुद्दा उठाते हुए कड़े कदम उठाने की मांग की। एडवोकेट फौजिया शकील और वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने अदालत को बताया कि दिल्ली ही नहीं, बल्कि बिहार समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शनकारी छात्रों पर अत्यधिक बल प्रयोग किया जा रहा है। वकीलों ने दावा किया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एके-47 और घातक हथियारों तक की मौजूदगी देखी गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि पूरे देश में प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक समान प्रोटोकॉल और रोक-टोक रहित व्यवस्था की आवश्यकता है, ताकि असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जा सके लेकिन आम छात्रों की आवाज को दबाया न जाए। अदालत में केवल छात्रों का पक्ष ही नहीं गूंजा, बल्कि हिंसा में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों का पक्ष रखने भी वकील पहुंचे।

BAMS का पेपर लीक,WhatsApp पर वायरल हुए 11 सवाल

गुजरात,27 जुलाई 2026। गुजरात में उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। देशभर में NEET परीक्षा को लेकर विवाद अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुआ था कि अब जामनगर स्थित प्रतिष्ठित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS परीक्षा के पेपर लीक होने के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी के तीसरे प्रोफेशनल ईयर के एक महत्वपूर्ण विषय का प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था। इस घटना ने न केवल विश्वविद्यालय प्रशासन बल्कि छात्रों और अभिभावकों की भी चिंता बढ़ा दी है। मामले के सामने आते ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 20 जुलाई को BAMS थर्ड प्रोफेशनल ईयर के MS-शल्य तंत्र-1 विषय की परीक्षा निर्धारित समय पर आयोजित की गई थी। परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और शुरुआत में किसी प्रकार की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली। लेकिन परीक्षा समाप्त होने के बाद कुछ छात्रों ने दावा किया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप के कई ग्रुपों में इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए गए थे। छात्रों के अनुसार, जब उन्होंने परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के बाद प्रश्नपत्र का मिलान व्हाट्सएप पर वायरल संदेशों से किया तो वे हैरान रह गए। दावा किया गया कि परीक्षा में पूछे गए कुल 12 प्रश्नों में से 11 प्रश्न वही थे,जो पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो चुके थे। इतनी अधिक समानता ने पेपर लीक की आशंका को और मजबूत कर दिया। देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया और शैक्षणिक जगत में चर्चा का विषय बन गया। पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विश्वविद्यालय के इंचार्ज एग्जामिनेशन डायरेक्टर डॉ. एच. पी. झाला ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि परीक्षा सुबह के सत्र में पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित हुई थी।

उन्हें शाम के समय सूचना मिली कि परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न साझा किए गए थे, जिनका परीक्षा के प्रश्नपत्र से काफी मेल बताया जा रहा है। डॉ. झाला ने कहा कि जैसे ही उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) को पूरे मामले से अवगत कराया।

संपादकीय

इस्तीफों के नफा-नुकसान

कॉ करोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के आंदोलन के बाद अंततः शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसे 'देर आयद दुरुस्त आयद' इसलिए नहीं कहा जा सकता,क्योंकि यहां तक आते-आते सरकार ने बहुत देर कर दी। सरकार के लिए राहत की बात बस इतनी कही जा सकती है कि जो छात्र आंदोलन गले की हड्डी बनता जा रहा था,वह फिलहाल के लिए तो खत्म हो गया है। इसी तरह सरकार इस मसले पर संसद के भीतर विपक्ष की लामबंदी के भी समाप्त होने की उम्मीद के साथ कुछ जरूरी विधयेकों को आगे बढ़ा सकती है।

जिस सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह बयान सदाबहार रहा हो कि इस सरकार में कभी इस्तीफे नहीं होते,वहां धर्मेंद्र प्रधान की रवानगी कई लोगों को हैरान करने वाली लग सकती है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस्तीफे के तुरंत बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके की यह हुंकार कि 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए'में अनेक लोग 'सरकार की पराजय' जैसे भावार्थ निकाल सकते हैं। हालांकि अगर इसे सरकार की हार मान भी लिया जाए तो विपक्ष के लिए भी यह कोई बहुत खुश होने का अवसर नहीं है। इसकी दो वजहें हैं-देश में कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि प्रधान ने इस्तीफा विपक्ष के दबाव में दिया। इसका पूरा श्रेय छात्रों के आंदोलन को ही दिया जा रहा है। प्रधान से इस्तीफा दिलवाकर सरकार ने एक तरह से विपक्ष से वह मुद्दा छीन लिया है,जो शिक्षा व्यवस्था में खामियों को लेकर बन सकता था और इससे सरकार और अधिक मुसीबतों से घिर सकती थी। अब माना जा सकता है कि सरकार पूरे मसले को रफा-दफा करके पूर्व वाली स्थिति में आ जाएगी। वह भविष्य में भी सीजेपी की बात ही ज्यादा सुनेगी,ताकि कांग्रेस और सपा जैसे प्रमुख विपक्षी दलों को नजरअंदाज करने का एक नैरेटिव बना सके।

इस पूरे परिप्रेक्ष्य में इस्तीफों के इतिहास को भी समझने के साथ ही इस्तीफों को लेकर सियासी नफा-नुकसान के बारे में जानना भी समीचीन होगा। एक तात्कालिक आम धारणा यही बनती है कि किसी राजनीतिक हस्ती के इस्तीफे का मतलब है उसके राजनीतिक करियर का खात्मा,लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। एमजे अकबर जैसे कतिपय उदाहरणों को छोड़ दें तो पता चलेगा कि जिस भी शख्स ने इस्तीफा दिया,उसने उसी ताकत के साथ वापसी भी की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो लाल बहादुर शास्त्री हैं। जब-जब भारतीय राजनीति में सार्वजनिक जवाबदेही और नैतिक मूल्यों की बात होती है,उनकी मिसाल सबसे पहले दी जाती है। वर्ष 1956 में जब शास्त्री देश के रेल मंत्री थे, उसी वर्ष तमिलनाडु में हुए एक भीषण रेल हादसे में 144 यात्रियों की मौत हो गई थी। शास्त्री जी ने हादसे की पूरी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, 1957 के आम चुनाव के बाद पंडित नेहरू ने उन्हें पुनः मंत्रिमंडल में शामिल कर परिवहन एवं संचार मंत्री बनाया। कालांतर में वे देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे।

त्यागपत्र और दमदार राजनीतिक वापसी के शास्त्री अकेले उदाहरण नहीं रहे। भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर यह क्रम कई बार दोहराया गया है। जनवरी 1993 में पीवी नरसिंह सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रहे माधवराव सिंधिया ने भी ऐसी ही मिसाल पेश की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के दौरान रूस से लीज पर लिया गया एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

आंदोलन,नेतृत्व और लोकतंत्र : सवालों के बीच सच्चाई की तलाश

प्रकाशक: दैनिक घटती घटना

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता,बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी,संवाद,असहमति और उत्तर दायित्व से भी संचालित होता है। किसी भी लोक तांत्रिक व्यवस्था में आंदोलन सामा जिक चेतना का माध्यम होते हैं। वे सत्ता को आईना दिखाते हैं,जनता की पीड़ा को स्वर देते हैं और नीतिगत सुधारों का मार्ग प्रशस्त करते हैं। किंतु इतिहास यह भी बताता है कि हर आंदोलन स्वतः पवित्र नहीं होता और न ही हर आंदोलन संदेह से परे होता है। यदि किसी आंदोलन के उद्देश्य, नेतृत्व,वित्तीय स्रोत,संगठनात्मक संरचना और कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठते हैं, तो उनका उत्तर भी लोकतांत्रिक पार दर्शिता के साथ दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार,किसी आंदोलन के विरुद्ध लगाए गए आरोपों का भी मूल्यांकन प्रमाणों के आधार पर होना चाहिए,न कि केवल राजनीतिक धारणाओं के आधार पर।

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

हाल के वर्षों में भारत में अनेक आंदोलनों ने राष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित किया है। किसान आंदोलन,नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध आंदोलन तथा युवाओं से जुड़े अनेक अभियान इसका उदाहरण हैं। इन आंदोलनों ने यह स्पष्ट किया कि देश का युवा वर्ग अपने अधिकारों और भविष्य के प्रश्नों पर मुखर है। साथ ही,इन आंदोलनों ने यह प्रश्न भी उठाया कि किसी जनांदोलन की वैधता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके संचालन की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व से भी तय होती है।

जब कोई नया चेहरा अचानक राष्ट्रीय स्तर पर उभरता है,सोशल मीडिया पर अल्प समय में अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त करता है या किसी बड़े आंदोलन का नेतृत्व करता दिखाई देता है,तो स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा उत्पन्न होती है। लोग उसके जीवन,पृष्ठभूमि, वैचारिक यात्रा,आर्थिक स्रोत और संगठनात्मक क्षमता के बारे में जानना चाहते हैं। लोकतंत्र में यह जिज्ञासा अनुचित नहीं है। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय व्यक्ति से सार्वजनिक जवाबदेही की अपेक्षा भी स्वाभाविक है। किंतु जिज्ञासा और आरोप के बीच एक स्पष्ट रेखा होती है। प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है,जबकि बिना प्रमाण किसी निष्कर्ष पर पहुँच जाना लोकतांत्रिक विवेक के विपरीत है। आज सोशल मीडिया ने राजनीति की प्रकृति बदल दी है। पहले लोकप्रियता वर्षों के संघर्ष से मिलती थी, अब कभी-कभी कुछ दिनों में लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच बन जाती है। एल्गोरिद्म, वायरल सामग्री,मीडिया कवरेज, समर्थकों के अभियान,विज्ञापन और डिजिटल नेटवर्क किसी व्यक्ति की पहुँच को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। इसलिए केवल अनुयायियों की संख्या देखकर किसी षड्यंत्र का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर यदि किसी डिजिटल अभियान में कृत्रिम प्रचार, बॉट नेटवर्क या अपारदर्शी संसाधनों के संकेत मिलते हैं,तो उनकी स्वतंत्र जाँच भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा होनी चाहिए।

लोकतंत्र में आंदोलन की सफलता केवल भीड़ की संख्या से नहीं मापी जाती। कई बार छोटे आंदोलन बड़े परिवर्तन का कारण बनते हैं और कई बार विशाल भीड़ भी स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाती। किंतु किसी आंदोलन में यदि हिंसा,सार्वजनिक संपत्ति की क्षति,पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव या उकसावे की घटनाएँ सामने आती हैं, तो उनकी निष्पक्ष जाँच आवश्यक हो जाती है। यह भी उतना ही आवश्यक है कि दोषियों की पहचान व्यक्तिगत जिम्मेदारी के आधार पर हो, न कि पूरे आंदोलन या पूरे समाज को एक ही रंग में रंग दिया जाए।

भारत का संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार देता है। साथ ही,राज्य पर यह दायित्व भी डालता है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे। इसलिए लोकतंत्र में आंदोलन और प्रशासन दोनों की परीक्षा होती है। यदि आंदोलन हिंसक होता है तो उसका नैतिक आधार कमजोर पड़ता है। यदि प्रशासन आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग करता है तो उसकी वैधता पर प्रश्न उठते हैं। संतुलन ही लोकतंत्र की पहचान है।

राजनीतिक दलों का आंदोलनों में शामिल होना भी भारतीय राजनीति की पुरानी परंपरा है। विपक्ष का काम केवल संसद में बहस करना नहीं,बल्कि जनता के बीच जाकर सरकार की नीतियों का विरोध करना भी है। इसी प्रकार सत्ता पक्ष का दायित्व केवल विरोध को राजनीतिक साज़िश बताना नहीं,बल्कि जनता के वास्तविक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करना भी है। लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष और उत्तरदायी सरकार दोनों समान रूप से आवश्यक हैं।

आंदोलनों के वित्तीय स्रोतों पर पारदर्शिता का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय तक चलने वाले धरने, मंच,प्रचार,परिवहन,भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इसलिए यह अपेक्षा अस्वाभाविक नहीं कि बड़े आंदोलनों के आयोजक अपने वित्तीय स्रोतों के प्रति पारदर्शी रहें। इसी प्रकार यदि किसी संगठन पर विदेशी फंडिंग या अन्य अवैध आर्थिक सहायता का आरोप लगाया जाता है,तो उसका निर्णय केवल वैधानिक जाँच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए। लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण समानार्थी नहीं होते।

भारत का युवा वर्ग आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप, भर्ती प्रक्रियाओं में विलंब,बेरोज़गारी और भविष्य की अनिश्चितता युवाओं में असंतोष पैदा करती है। यदि इन वास्तविक समस्याओं का समाधान समय पर न हो, तो कोई भी आंदोलन व्यापक समर्थन प्राप्त कर सकता है। इसलिए सरकारों के लिए सबसे बड़ा उत्तर आंदोलन को दबाना नहीं, बल्कि उन कारणों का समाधान करना है जो आंदोलन की पृष्ठभूमि बनते हैं।

उधर आंदोलनकारियों की भी जिम्मेदारी कम नहीं है। यदि आंदोलन किसी विशेष मुद्दे पर है,तो उसका फोकस उसी मुद्दे पर रहना चाहिए। यदि विभिन्न असंबंधित राजनीतिक या वैचारिक एजेंडे उसमें शामिल होने लगें,तो आम नागरिकों के मन में भ्रम उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि किसी भी जनांदोलन की विश्वसनीयता उसके अनुशासन,स्पष्ट उद्देश्य और शांतिपूर्ण चरित्र से बनती है। भारत का लोकतंत्र अनेक उतार-चढ़ावों से गुजरा है। इस देश ने आपातकाल भी देखा है और शांतिपूर्ण जनांदोलन भी। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने का मार्ग न तो अंध-समर्थन है और न ही अंध-विरोध। लोकतंत्र की शक्ति आलोचनात्मक विवेक में निहित है। नागरिकों को सरकार से भी प्रश्न पूछने चाहिए और आंदोलनकारियों से भी। मीडिया को भी दोनों पक्षों की समान गंभीरता से पड़ताल करनी चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता बढ़े। जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व का दावा करता है,उसे अपनी पृष्ठभूमि,संगठना त्मक ढाँचे और संसाधनों के बारे में स्पष्ट जानकारी देने में संकोच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार सरकारों को भी आलोचना को राष्ट्रविरोध मानने के बजाय लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा समझना चाहिए। प्रश्न पूछना लोकतंत्र की आत्मा है,पर उत्तर साक्ष्यों पर आधारित होने चाहिए।

लोकतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि हम मतभेदों को संवाद में बदल पाते हैं या नहीं। यदि हर विरोध को षड्यंत्र और हर सरकार को शत्रु मान लिया जाएगा,तो लोकतांत्रिक संस्थाएँ कमजोर होंगी। वहीं यदि हर प्रश्न को देशद्रोह या हर आलोचना को विदेशी एजेंडा कहकर खारिज कर दिया जाएगा,तब भी लोकतंत्र का नुकसान होगा।भारत जैसा विशाल और विविधतापूर्ण राष्ट्र केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि संस्थाओं, संविधान और नागरिक विवेक से चलता है। इसलिए किसी भी आंदोलन,नेता या सरकार के बारे में अंतिम निर्णय तथ्यों, प्रमाणों और निष्पक्ष जाँच पर आधारित होना चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति न तो भीड़ है और न सत्ता, बल्कि सत्य है। सत्य तक पहुँचने का मार्ग प्रश्नों से होकर अवश्य जाता है, किंतु उन प्रश्नों के उत्तर प्रमाणों से ही मिलते हैं। यही लोकतंत्र की परिपक्वता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी।

धरती की चेतावनी को सुनिए,प्रकृति का धैर्य अब जवाब दे रहा है...

प्रकृति से युद्ध नहीं, संवाद होना चाहिए...

पूरी दुनिया में मौसम के तेजी से बिगड़ते मिजाज के कारण विभिन्न देशों में प्रकृति की मार अब स्पष्ट नजर आने लगी है। प्रकृति के साथ खिल वाड़ का ही परिणाम है कि अब हर साल देश के कई हिस्से भारी बारिश के कारण बाढ़ की वजह से त्राहि-त्राहि करते नजर आते हैं जबकि कई हिस्से मानसून के दौरान भी पर्याप्त बारिश के लिए तरसते रह जाते हैं। इस वर्ष भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। दुनिया के कई ठंडे इलाके अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण तपने लगे हैं तो कई सूखे इलाके बाढ़ से त्रस्त हैं,जंगल झुलस रहे हैं। बिगड़ते पर्यावरणीय संतुलन और मौसम चक्र में आते बदलाव के कारण पेड़-पौधों की अनेक प्रजातियों के अलावा जीव-जंतुओं की कई प्रजातियों के अस्तित्व पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पर्यावरण के तेजी से बदलते इस दौर में वैश्विक स्तर पर लोगों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकृष्ट करने के लिए ही प्रतिवर्ष 28 जुलाई को 'विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस' मनाया जाता है,जिसके माध्यम से

योगेश कुमार गोयल
नजफ़गढ़,
नई दिल्ली

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

वातावरण में हो रहे व्यापक बदलावों के चलते लगातार विलुप्ति के कगार पर पहुंच रही जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक प्रजातियों की रक्षा का संकल्प लिया जाता है। विश्वभर में आधुनिकी करण और औद्योगिकीकरण के चलते प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर जो खिलवाड़ हो रहा है, उसके मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिहाज से आज के समय में प्रकृति संरक्षण दिवस की महत्ता बढ़ गई है।

2020 में कोरोना महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौर में पूरी दुनिया ने पहली बार प्रकृति को खुलकर मुस्कराते देखा था क्योंकि तब औद्योगिक इकाईयां,हवाई व रेल यात्राएं,बस यात्रा तथा निजी वाहनों का आवागमन बंद होने से हर तरह के प्रदूषण का स्तर पूर्ण रूप से नियंत्रित हो गया था। गंगा,यमुना जैसी जो पवित्र नदियां कई जगहों पर गंदे नालों की भांति बहती दिखाई देती थी,उनमें जल की निर्मल धारा बहने लगी थी। जिन नदियों को साफ करने के लिए पिछले कुछ दशकों में अनेक योजनाएं और समितियां बनी तथा नदियों की स्वच्छता के नाम पर अरबों-खरबों रुपये खर्च हो गए,लॉकडाउन के दौरान वे स्वतः ही स्वच्छ और निर्मल हो गई थी। पहली बार देखा गया था कि किस प्रकार लॉकडाउन के चलते लोगों के घरों में बंद रहने और सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्य बंद हो जाने से हवा इतनी शुद्ध हो गई थी कि सैंकड़ों किलोमीटर दूर स्थित पर्वतों की चोटियां भी स्पष्ट दिखाई दी थी। जिन नन्हीं चिड़ियों की चहचहाहट को हमारे कान तरस गए थे,ब्रह्म मुहूर्त में उनकी मधुर आवाज फिर से सुनाई देनी लगी थी। प्रकृति के उस साफ-सुथरे स्वरूप को देखकर हर कोई खुश था। दरअसल प्रकृति को स्वयं अपनी मरम्मत करने और खुद को सजाने-संवारने का सुअवसर मिला था लेकिन इंसानी गतिविधियां पुनः शुरू होते ही प्रकृति के साथ निर्मम खिलवाड़ का वही दौर पुनः शुरू हो गया, जिसका परिणाम इस समय दुनिया के तमाम देश भुगत रहे हैं। लॉकडाउन के दौर ने पूरी दुनिया को यह समझने का बेहतरीन अवसर दिया था कि इंसानी गतिविधियों के कारण ही प्रकृति का जिस बड़े पैमाने पर दोहन किया जाता रहा है,उसी के कारण स्वर्ग से भी सुंदर हमारी धरती कराहती रही है। प्रकृति मनुष्य को ऐसा न करने के लिए बार-बार किसी न किसी बड़ी आपदा के रूप में चेतावनियां भी देती रही है लेकिन उन चेतावनियों को सदा दरकिनार किया जाता रहा है। प्रकृति के साथ मानवीय छेड़छाड़ का ही नतीजा रहा है कि बीते कुछ वर्षों में मौसम चक्र में बदलाव स्पष्ट दिखाई दिया है। वर्ष दर वर्ष अब जिस प्रकार मौसम के बिगड़ते मिजाज के चलते समय-समय पर तबाही देखने को मिल रही है,ऐसे में हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि मौसम चक्र के बदलाव के कारण प्रकृति संतुलन पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है,उसकी अनदेखी के कितने भयावह परिणाम होंगे। प्रकृति बार-बार मौसम चक्र में बदलाव के संकेत, चेतावनी तथा संभलने का अवसर देती रही है लेकिन हम आदतन किसी बड़े खतरे के सामने आने तक ऐसे संकेतों या चेतावनियों को नजरअंदाज करते रहे हैं, जिसका नतीजा अक्सर भारी तबाही के रूप में सामने आता रहा है। पिछले तीन दशकों से पर्यावरण प्रदूषण के कारण जिस प्रकार मौसम चक्र तीव्र गति से बदल रहा है और प्राकृतिक आपदाओं का आकस्मिक सिलसिला तेज हुआ है, उसके बावजूद यदि हम नहीं संभलना चाहते तो इसमें भला प्रकृति का क्या दोष? प्रकृति के साथ हम बड़े पैमाने पर जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि पिछले कुछ समय में भयानक तूफानों,बाढ़,सूखा,भूकम्प जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सिलसिला तेजी से बढ़ा है। अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि किस प्रकार पर्यावरण का संतुलन डगमगाने के चलते लोग अब तरह-तरह की भयानक बीमारियों के जाल में फंस रहे हैं। हमारे जो पर्वतीय स्थान कुछ सालों पहले तक शांत और स्वच्छ वातावरण के कारण हर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया करते थे, आज वहां भी प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है और ठंडे इलाकों के रूप में विख्यात पहाड़ भी तपने लगने हैं, वहां भी जल संकट गहराने लगा है। दरअसल पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात के साधनों से बढ़ते प्रदूषण, बड़े-बड़े उद्योग स्थापित करने और राजमार्ग बनाने के नाम पर बड़े पैमाने पर वनों के दोहन,सुरंगें बनाने के लिए बेदर्दी से पहाड़ों का सीना चीरे जाने का ही दुष्परिणाम है कि हमारे इन खूबसूरत पहाड़ों की ठंडक अब लगातार कम हो रही है। पहाड़ों में बढ़ती इसी गर्माहट के चलते हमें अक्सर घने वनों में भयानक आग लगने की खबरें भी सुनने को मिलती रहती हैं। पहाड़ों की इसी गर्माहट का सीधा असर निचले मैदानी इलाकों पर पड़ता है, जहां का पारा अब वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है।

हालांकि प्रकृति बार-बार अपना रौद्र रूप दिखाकर स्पष्ट चेतावनी देती रही है कि यदि उसके साथ अंधाधुंध खिलवाड़ बंद नहीं हुआ तो उसके घातक परिणाम होंगे लेकिन विड़म्बना है कि लगातार प्रकृति का प्रचण्ड रूप देखते रहने के बावजूद प्रकृति की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दुनिया अपने विनाश को आमंत्रित कर रही है। दरअसल हम समझना ही नहीं चाहते कि पहाड़ों का सीना चीरकर हरे-भरे जंगलों को तबाह कर हम कंक्रीट के जो जंगल विकसित कर रहे हैं,वह वास्तव में विकास नहीं है बल्कि विकास के नाम पर हम अपने ही विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रकृति कभी समुद्री तूफान तो कभी भूकम्प,कभी सूखा तो कभी अकाल के रूप में अपना विकराल रूप दिखाकर हमें बारम्बार चेतावनी देती रही है कि हम यदि इसी प्रकार प्राकृतिक संसाधनों का बुरे तरीके से दोहन करते रहे तो हमारे भविष्य की तस्वीर कैसी होने वाली है। यदि हम अभी भी नहीं संभले और हमने प्रकृति से साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया तो हमें आने वाले समय में इसके खतरनाक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।

जनता और सरकार के बीच सामंजस्य प्रगति की सही राह

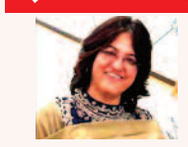

केशी गुप्ता
द्वारका
दिल्ली

भारत की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में हो रहा युवा आंदोलन,जो कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक द्वारा शुरू किया गया था,25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के साथ समाप्त हो गया। लोकतंत्र का विजय उद्घोष देश भर में बज उठा । हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी के निर्माता अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरभ का कहना है कि अभी बहुत से मुद्दे है जिन पर बातचीत,संशोधन जरूरी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े के बाद नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी का चयन कर दिया गया है। नीट पेपर लीक को लेकर कड़े कदम उठाये जाने का दावा किया जा रहा है और शिक्षा से सम्बन्धित कई पदों में नियुक्त अधिकारियों का बर्खास्त कर नई नियुक्तियां की गई है । इस आंदोलन ने समस्त युवा पीढ़ी को जगा दिया है । इस आंदोलन को ले कर अलग अलग मत सामने आ रहे है । कुछ लोग इस आंदोलन को राजनैतिक उथल पुथल से जोड़ रहे है तो कुछ ऑपोजिशन की चाल बता रहे है । आवाम का कहना है कि सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा काफी नहीं है देश के अभी बहुत से मुद्दे है जिन पर मौजूदा सरकार की जवाबदारी बनती है। इथेनॉल मुद्दे को लेकर भी आवाम में आक्रोश और गुस्सा है । जनता 100 प्रतिशत पेट्रोल की मांग करती दिखाई दे रही है। यदि साइंस के तथ्यों को खंगाला जाए तो इथेनॉल का इस्तेमाल अत्यंत हानि कारक है । तथाकथित तथ्यों पर आधारित इसको बनाने की प्रक्रिया में जो वेस्ट निकलता है वह सड़न भरा है जो नदियों ,धरती में मिलकर जहर का काम करेगा। आज आवाम मौजूदा सरकार के प्रति खुल कर अपना असंतोष व्यक्त कर रही है । देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग आंदोलन चल रहे है। समय आ गया है जब देश से जुड़ी हर समस्या जैसे ईवीएम,पर्यावरण , महंगाई,इथेनॉल,कानूनव्यवस्था, बेरोजगारी,स्वास्थ्य सब पर एक नए सिरे से विचार विर्मश कर खुल कर बात हो और उसके समाधान की तरफ सकारात्मक कदम उठाए जाए। जनता और सरकार के बीच सही सामंजस्य ही देश की प्रगति का सही रास्ता है।

परिवार परम्परा एवं बिखरते रिश्ते पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता

परिवार केवल एक छत के नीचे रहने वाले लोगों का समूह नहीं,बल्कि विश्वास, त्याग, धैर्य और संस्कारों का जीवंत विद्यालय है। जब इस विद्यालय की नींव कमजोर होने लगती है तो उसका प्रभाव केवल एक घर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। देश के बहुचर्चित सोनम रघुवंशी 'हनीमून मर्डर' प्रकरण की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ द्वारा व्यक्त की गई चिंता केवल एक अपराध पर की गई टिप्पणी नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के बदलते चरित्र का गहन सामाजिक विश्लेषण थी। न्यायमूर्ति एम.एम.सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी. बी. वराले ने जिस पीड़ा के साथ कहा कि संयुक्त परिवार लोगों को धैर्य, संयम,सहनशीलता और समायोजन सिखाते थे,वहीं आज एकल परिवारों में अवसाद,असहिष्णुता और संबंधों का विघटन बढ़ रहा है,वह हमारे समय का कटु सत्य है।

डॉ. ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

माता-पिता और संतान,भाई-बहन, दादा-दादी और पोते-पोतियों के बीच भी भावनात्मक दूरी लगातार बढ़ रही है, यह परिवार परम्परा एवं रिश्तों में बढ़ती दूरी अब पति-पत्नी के बीच भी बड़ी दरारें डालने लगी है। रिश्तों का खोखलापन इतना बढ़ गया है कि अपनी ही पत्नी या पति की हत्या करने में भी तनिक संकोच नहीं रहा। ऐसे घटनाएं बार-बार देखने को मिल रही है। घर बड़े हो गए हैं, लेकिन दिल छोटे होते जा रहे हैं। सुविधाएं बढ़ी हैं,परंतु संवेदनाएं सिकुड़ती जा रही हैं। संवाद कम हो गए हैं और स्क्रीन का समय बढ़ गया है। परिणामस्वरूप रिश्ते धीरे-धीरे औपचारिकता में बदलते जा रहे हैं। हाल के वर्षों में विवाह से पहले अथवा विवाह के कुछ ही दिनों बाद हुई इन नृशंस हत्याओं ने पूरे देश को झकझोर दिया है। यह केवल कानून-व्यवस्था का प्रश्न नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना के पतन का संकेत है। जिन परिवारों में धन, प्रतिष्ठा और भौतिक सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, वहीं जीवन का सबसे बड़ा अभाव विश्वास और संतोष का था। संत कबीर का यह वचन आज पहले से अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है-'जब आए संतोष धन,सब धन धूरि समान।' भौतिक संपन्नता कभी भी मानसिक शांति और रिश्तों की ऊष्मा नहीं खरीद सकती।

भारतीय संस्कृति ने परिवार को केवल सामाजिक संस्था नहीं माना, बल्कि धर्म, संस्कृति और जीवन-मूल्यों का प्रथम विद्यालय माना है। संयुक्त परिवार में दादा-दादी केवल बुजुर्ग नहीं होते थे, वे अनुभवों के विश्वविद्यालय होते थे। नाना-नानी केवल रिश्तेदार नहीं, बल्कि संस्कारों के संरक्षक होते थे। बच्चों को कहानियों के माध्यम से धैर्य, करुणा,क्षमा, संयम और त्याग का पाठ पढ़ाया जाता था। घर का हर सदस्य दूसरे के दुःख का सहभागी होता था। इसलिए किसी एक व्यक्ति का तनाव पूरे परिवार की शक्ति से हल्का हो जाता था। आज यह सुरक्षा-कवच तेजी से टूट रहा है। महत्वाकांक्षाओं की अंधी दौड़ में पति-पत्नी दोनों कार्यस्थल पर व्यस्त हैं। बच्चों का बचपन मोबाइल, टैबलेट और घरेलू सहायिकाओं के भरोसे बीत रहा है। जब बच्चा रोता है तो उसे गोद नहीं, मोबाइल थमा दिया जाता है। यह सुविधा का समाधान नहीं, संवेदनाओं का विस्थापन है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी कि 'भावनाओं का विकल्प गैजेट्स नहीं हो सकते', हमारे समय की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक चेतावनी है।

एक बाप की डायरी

बाप अक्सर अपनी ज़रूरत नहीं,अपनी औलाद का मुस्तकबिल देखता है...

डॉ. मुश्ताक़ अहमद शाह सहज़
हरदा,मध्यप्रदेश

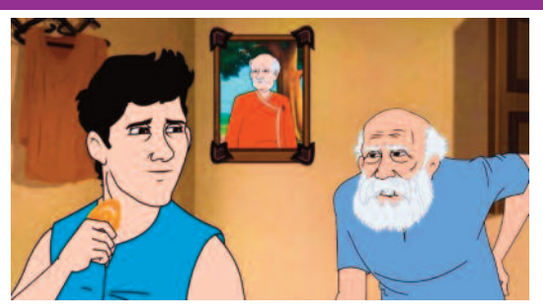

शाम का वक्त था, कमरे में मद्धम रोशनी जल रही थी। मेज़ पर अबू की पुरानी डायरी रखी थी,जिसके सफ़हात वक्त की गर्द तले दबे हुए थे। अरमान ने जब वो डायरी खोली,तो उसके अंदर छुपा हुआ दर्द उसके सीने में उतरता चला गया,

अरमान हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठा अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए फोन पर बात कर रहा था। उसे इस माह भी कॉलेज की फ़ीस और दीगर अख़राजत के लिए पैसों की ज़रूरत थी। वो सीधा अपने अबू के कमरे में गया और बोला।

अबू! इस माह के अख़राजत और फ़ीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे, कल आख़िरी तारीख़ है।

मास्टर हबीब ने खांसते हुए अपनी जेब से पर्स निकाला,उसमें से कुछ मुड़े-तुड़े नोट निकालकर अरमान के हाथ पर रख दिए और नर्मी से बोले,

ये लो बेटा...अपना ख्याल रखना और पढ़ाई दिल लगाकर करना।

अरमान ने पैसे पकड़े और बग़ैर यह सोचे कि उस बूढ़े बाप के पास यह रक़म कहाँ से आई है, कमरे से बाहर निकल गया। उसे क्या मालूम था कि उसके बाप की यह मुस्कुराहट कितनी महँगी पड़ रही है।

कुछ ही दिनों बाद,एक अनहोनी हुई,मास्टर हबीब अचानक इस दुनिया से रुख़सत हो गए। घर में कोहराम मच गया। अरमान सदमे की हालत में था, पूरा घर ताज़ियत करने वालों से भरा हुआ था।

तदफ़ीन और रस्म-ए-चहलम के बाद जब अरमान अपने अबू की अलमारी की सफ़ाई कर रहा था, तो उसके हाथ एक पुरानी, फटी हुई डायरी लगी। उसने तजस्सुस के साथ डायरी का पहला सफ़्हा खोला। अंदर अबू की जानी-पहचानी और थकी हुई लिखावट में दर्ज था,

बेटा हर माह अबू से पैसे लेता रहा...मैंने अपनी दवा लेना छोड़ दी थी... ताकि मेरे बेटे की फ़ीस न रुके।

डायरी का यह जुमला पढ़ते ही अरमान के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा गया और वहीं फ़र्श पर बैठकर फूट-फूट कर रोने लगा। उसे वो तमाम दिन याद आ गए जब वो बिला झिझक पैसे माँगता था और अबू हमेशा मुस्कुराकर दे दिया करते थे।

उसे अब समझ आया कि वो गोलियाँ जो अबू रोज़ाना खाया करते थे, पिछले कई महीनों से क्यों बंद थीं,क्योंकि उन गोलियों के पैसों से उसका मुस्तकबिल संवर रहा था।

कमरा बिल्कुल ख़ामोश था,बस अरमान की सिसकियाँ गूँज रही थीं और दिल ही दिल में वो अपने बाप के सामने शर्मिंदा हो रहा था,यह सोचकर कि...

बाप अक्सर अपनी ज़रूरत नहीं,अपनी औलाद का मुस्तकबिल देखता है..।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

बिजली कटौती नहीं,निगम की लापरवाही से प्यासा शहर?

फिल्टर प्लांटों की बदहाली पर कांग्रेस का बड़ा हमला,कलेक्टर से कहा...जिम्मेदार अफसरों पर हो कार्रवाई,नहीं तो होगा आंदोलन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

कभी स्वच्छता और बेहतर शहरी प्रबंधन के लिए देशभर में पहचान बनाने वाला अंबिकापुर आज पेयजल संकट,बदहाल सफाई व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइटों और जर्जर सड़कों की समस्याओं से जूझ रहा है। इन मुद्दों को लेकर सोमवार को कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए नगर निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि शहर में जल संकट का कारण केवल बिजली कटौती नहीं, बल्कि नगर निगम की खराब कार्यप्रणाली और फिल्टर प्लांटों की अनदेखी है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षदों ने ज्ञापन सौंपने से पहले शहर को पानी उपलब्ध कराने वाले तकिया और कतकालो फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कांग्रेस ने दावा किया कि दोनों प्लांट अपनी निर्धारित क्षमता से काफी कम पानी का शोधन कर रहे हैं। मड पंप लंबे समय से खराब पड़े हैं, छह क्लैरिफ्लोकुलेटरों में से तीन बंद हैं, फिल्टर बेड की नियमित सफाई नहीं हो रही, फिटकरी की कमी है और तकनीकी कर्मचारियों का भी अभाव है।

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि अब तक नगर निगम प्रशासन पेयजल संकट के लिए बिजली कटौती को जिम्मेदार बताता रहा, लेकिन निरीक्षण में वास्तविक स्थिति कुछ और ही सामने आई। उनके अनुसार समस्या की जड़ खराब रखरखाव, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक उदासीनता है। यदि समय रहते आवश्यक मरम्मत और रखरखाव किया गया होता तो शहरवासियों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। कांग्रेस ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। ज्ञापन में कहा गया कि जिस अंबिकापुर की स्वच्छता व्यवस्था कभी राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल मानी जाती थी, वहीं पिछले डेढ़ वर्षों में हालात लगातार बिगड़ते गए हैं। कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही, जिससे आम नागरिकों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शहर की अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, अनेक सड़कें बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं और जिन सड़कों के निर्माण के टेंडर छह माह पहले हो चुके हैं, उनका काम अब तक शुरू नहीं हुआ। सवाल यह भी उठाया गया कि आखिर विकास कार्यों में यह देरी किसकी जिम्मेदारी है और इसके लिए जवाबदेही कब तय होगी? कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर से फिल्टर प्लांटों की तकनीकी जांच,बंद उपकरणों की तत्काल मरम्मत, पर्याप्त तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति, नियमित एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, सफाई व्यवस्था में सुधार,बंद स्ट्रीट लाइटों को चालू कराने,जर्जर सड़कों की मरम्मत तथा संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। चेतावनी दी गई कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो कांग्रेस जनहित में व्यापक आंदोलन शुरू करेगी। प्रतिनिधिमंडल में ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल,पार्षद हसन खान,पापिंदर सिंह, मोहम्मद बाबर,मोहम्मद अख्तर चम्मा,शुभम जायसवाल,जेनेविवा कुजूर,लूकस एक्का,मंडल अध्यक्ष अमित सिन्हा तथा बालकेश्वर तिर्की सहित अन्य कांग्रेसजन उपस्थित रहे।

बढ़े बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और कटौती के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन तेज करने का ऐलान

टी.एस. सिंहदेव बोले...जनता के मुद्दों को बनाएं प्राथमिकता,हर वार्ड से जुटाए जाएंगे बिजली बिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बढ़े हुए बिजली बिल, स्मार्ट मीटर और लगातार हो रही बिजली कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस अब बड़े जनआंदोलन की तैयारी में जुट गई है। सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित अंबिकापुर शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में आंदोलन की रणनीति तय की गई। बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक और नगर निगम नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह धंजल ने की। उन्होंने हाल ही में मंडल एवं ब्लॉक कार्यकारिणी की बैठकों में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने और आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता हैं। संगठन जितना मजबूत होगा,जनता का विश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से वार्ड, मतदान केंद्र और अनुभाग स्तर तक सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देने तथा कांग्रेस की विचारधारा को घर-घर पहुंचाने का आह्वान किया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा कि संगठन की मजबूती ही भविष्य की सफलता की आधारशिला है। उन्होंने सभी मंडल और ब्लॉक पदाधिकारियों को नियमित बैठकें आयोजित करने तथा जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने के निर्देश दिए। साथ ही मंडल अध्यक्षों से कहा कि वे स्मार्ट मीटर और बढ़े हुए बिजली बिल से परेशान उपभोक्ताओं से मिलकर उनके बिजली बिल एकत्र करें, ताकि इन मुद्दों को लेकर व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जा सके। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने कहा कि कांग्रेस जनसमस्याओं को लेकर सड़क से लेकर सदन तक लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हर वार्ड और मोहल्ले में

सक्रिय रहकर आम लोगों की आवाज बनने का आह्वान किया और कहा कि मजबूत संगठन के बल पर कांग्रेस जनता के हितों की लड़ाई और प्रभावी ढंग से लड़ेगी। बैठक में ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष विनय शर्मा,जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम,जिला महामंत्री हेमंत तिवारी,अशफाक अली,आलोक सिंह,सेवादल अध्यक्ष लवकेश पासवान,जिला प्रवक्ता आशीष वर्मा,जीवन यादव,मंडल अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश सिंह 'मग्गू',रजनीश सिंह,गुरप्रीत सिद्धू,निक्की खान,सोहन जायसवाल,शंकर प्रजापति,अमित सिन्हा,सौरभ फिलिप,बालकेश्वर तिर्की,दिनेश शर्मा,नरेंद्र विश्वकर्मा सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सरगुजा पुलिस का बैंक,एटीएम और ज्वेलर्स पर औचक सुरक्षा अभियान

संदिग्धों से कड़ी पूछताछ,सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में वित्तीय संस्थानों और आभूषण दुकानों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस ने सोमवार को विशेष अभियान चलाया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देश पर जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित राष्ट्रीयकृत एवं निजी बैंकों, एटीएम, ज्वेलर्स दुकानों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ भी की गई। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बैंक प्रबंधकों और प्रतिष्ठानों के संचालकों को सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्हें उच्च गुणवत्ता (हाई फ्रीक्वेंसी) के सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने, सुरक्षा गार्ड की पर्याप्त तैनाती सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक गतिविधि पर सतत निगरानी रखने को कहा गया। साथ ही सुरक्षा पंजी में दर्ज टिप्पणियों का पालन करने और बैंक परिसर के बाहर भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए। पुलिस टीम ने बैंक एवं ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों के आसपास अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों से पूछताछ की तथा परिसर में मौजूद संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन किया। संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल डायल-112 या संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारी को दें। अभियान के दौरान बैंक प्रबंधकों को वित्तीय संस्थानों में आपातकालीन अलार्म सिस्टम स्थापित करने की भी सलाह दी गई,ताकि संस्थान बंद होने के बाद किसी भी अनधिकृत प्रवेश या आपराधिक गतिविधि की तत्काल जानकारी मिल सके और समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जा सके। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल ने पुलिस पेट्रोलिंग टीमों को भी जिले के सभी बैंक, एटीएम और ज्वेलर्स दुकानों के आसपास नियमित एवं प्रभावी गश्त करने, संदिग्ध व्यक्तियों पर पैनी नजर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सरगुजा पुलिस का यह अभियान जिले में वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा मजबूत करने और संभावित आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से चलाया गया।

श्रीगढ़ भूमि विवाद: उच्च न्यायालय में विचाराधीन

जिला प्रशासन ने दी सफाई...चांदमारी शासकीय भूमि पर अंतिम कोर्ट फैसला के बाद...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026(घटती-घटना)।

सोशल मीडिया में प्रसारित उस खबर के बाद,जिसमें प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर द्वारा अपर कलेक्टर को सिविल जेल भेजने तथा कलेक्टर के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्ताव भेजने संबंधी कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की बात कही गई थी,जिला प्रशासन ने पूरे मामले की वस्तुस्थिति स्पष्ट की है।

प्रशासन के अनुसार,यह मामला ग्राम श्रीगढ़ स्थित भूमि के बंटवारे से जुड़ा है। व्यवहार वाद क्रमांक 02अ/1989 में तत्कालीन जिला न्यायाधीश ने 19 मार्च 1991 को खसरा क्रमांक 165, 186, 15/1 एवं 19/1 की कुल 3.66 एकड़ भूमि तथा मकान के विधिवत बंटवारे का आदेश पारित किया था। प्रशासन ने बताया कि इससे पहले ही 31 मार्च 1962 को ग्राम श्रीगढ़ की कुल 6.32 एकड़ भूमि तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन ने चांदमारी (पुलिस फायरिंग प्रशिक्षण) के लिए विधिवत पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से ₹1500 का भुगतान कर खरीदी थी। संबंधित भूमि का उपयोग आज भी चांदमारी प्रयोजन के लिए किया जा रहा है और इस विक्रय पत्र को आज तक किसी सक्षम न्यायालय ने निरस्त नहीं किया है।

हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका लंबित

प्रशासन के अनुसार,राज्य शासन ने इस मामले में वर्ष 2017 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में रिव्यू पिटिशन क्रमांक 107/2017 दायर की है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। इसलिए चांदमारी प्रयोजन में उपयोग हो रही शासकीय भूमि के संबंध में अंतिम निर्णय उच्च न्यायालय अथवा राज्य शासन के निर्णय के बाद ही लिया जाएगा।

कलेक्टर और अपर कलेक्टर को नोटिस

प्रशासन ने बताया कि व्यवहार न्यायालय के आदेश का पालन नहीं होने पर प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, अम्बिकापुर ने 17 अप्रैल 2026 को अपर कलेक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर सिविल जेल भेजे जाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। वहीं 23 जुलाई 2026 को कलेक्टर सरगुजा को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय की अवमानना के संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराने की बात कही गई।

शासन का पक्ष नहीं सुने जाने का दावा...

जिला प्रशासन का कहना है कि वर्ष 1989 के व्यवहार वाद में तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन और तत्कालीन कलेक्टर को पक्षकार बनाया गया था,लेकिन शासन को वाद की सूचना नहीं दी गई और न ही उसका पक्ष सुना गया। प्रशासन का आरोप है कि वादी ने न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत नहीं किया कि संबंधित भूमि पहले ही शासन द्वारा विधिवत खरीदी जा चुकी थी। साथ ही,लगभग 21 वर्ष बाद वाद के निष्पादन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।

भूमि बंटवारे का आंशिक आदेश जारी

जिला प्रशासन ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर ने 3 जुलाई 2025 को जांच के बाद नायब तहसीलदार को विधि अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके तहत 27 जुलाई 2026 को सक्षम राजस्व न्यायालय ने ग्राम श्रीगढ़ की खसरा क्रमांक 165/1 एवं 186/1 की कुल 1.047 हेक्टेयर भूमि का तीन समान भागों में बंटवारा करने का आदेश पारित कर दिया है। हालांकि, चांदमारी प्रयोजन में उपयोग हो रही खसरा क्रमांक 15/1 एवं 19/1 की शासकीय भूमि को इस आदेश से अलग रखा गया है, क्योंकि उसका विवाद अभी उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

टैटू और कपड़ों से हुई पहचान,पुलिस ने फिरौती के मैसेज को बताया साइबर ठगी का प्रयास

लापता युवक की मिली लाश,पहले आया था 1 लाख की फिरौती का मैसेज

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

11 जुलाई से लापता मायापुर निवासी 37 वर्षीय शुभम कश्यप का शव दो दिन पहले महामाया पहाड़ पर फंदे से लटका मिला था। अब शव की पहचान होने के साथ ही एक नया पहलू भी सामने आया है। परिजनों का कहना है कि युवक के लापता रहने के दौरान उनके मोबाइल पर एक संदेश आया था, जिसमें शुभम को एक युवती के पास होने का दावा करते हुए उसे वापस लाने के लिए एक लाख रुपए की मांग की गई थी। हालांकि पुलिस ने इसे प्रथम दृष्टया साइबर ठगी का प्रयास बताया है। शनिवार दोपहर वन विभाग के कर्मचारियों ने महामाया पहाड़ पर सड़ी-गली अवस्था में फंदे से लटका शव देखा और इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की। लगातार बारिश और लंबे समय तक शव पड़े रहने के कारण उसका निचला हिस्सा गल चुका था। घटनास्थल से

चप्पल, कपड़े और कुछ दवाइयां भी बरामद हुईं। मायापुर निवासी शुभम कश्यप 11 जुलाई से लापता था।

परिजनों ने 13 जुलाई को कोतवाली थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शव मिलने की सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और कपड़ों तथा कंधे पर बने टैटू के आधार पर उसकी पहचान की।

शुभम को थी नशे की लत

परिजनों के अनुसार शुभम नशे का आदी था। 10 जुलाई को नशे की आदत छुड़ाने और उसे समझाने के उद्देश्य से वे उसे कोतवाली भी लेकर गए थे, ताकि पुलिस की सख्ती का असर उस पर पड़े। अगले दिन वह घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा।

1 लाख रुपए का आया था मैसेज

शुभम की मां ने बताया कि तीन दिन पहले उनके मोबाइल पर एक संदेश आया था, जिसमें लिखा था कि शुभम एक युवती के पास है और उसे वापस लाना है तो एक लाख रुपए की व्यवस्था करनी होगी। इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई थी। कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा ने बताया कि गुमशुदगी के मामलों में इस तरह के फर्जी कॉल और संदेश पहले भी सामने आ चुके हैं। साइबर सेल से संदेश की जांच कराई गई, जिसमें यह ठगी का प्रयास प्रतीत हुआ। पुलिस का कहना है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जांच जारी है।

तलाश में अपेक्षित तेजी नहीं

वहीं परिजनों ने आरोप लगाया है कि गुमशुदगी दर्ज होने के बाद भी युवक की तलाश में अपेक्षित तेजी नहीं दिखाई गई। उनका कहना है कि यदि शुरुआती दिनों में व्यापक खोजबीन होती तो मामले की सच्चाई पहले सामने आ सकती थी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बस किराया बढ़ाने की मांग,नहीं तो 14 अगस्त के बाद प्रदेशभर में थम जाएंगे पहिए

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

बढ़ती परिचालन लागत और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि को लेकर छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ ने यात्री बस किराए में संशोधन की मांग तेज कर दी है। महासंघ ने सोमवार को जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य शासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 31 जुलाई तक किराया संशोधित नहीं किया गया तो 3 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद भी मांगें पूरी नहीं होने पर 14 अगस्त के बाद पूरे प्रदेश में बसों का संचालन अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा सकता है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2021 के बाद से बस संचालन की लागत लगातार बढ़ी है। डीजल,स्पेयर पार्ट्स,टायर,बीमा, फिटनेस, टैक्स और चालक-परिचालकों के वेतन सहित अन्य खर्चों में भारी वृद्धि हुई है। इसके बावजूद मार्च 2025 में यात्री किराए में करीब 25 प्रतिशत की कमी कर दी गई, जिससे परिवहन व्यवसाय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। बस संचालक अंशुल श्रीवास्तव ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पुराने किराए पर बसों का संचालन करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2021 की किराया व्यवस्था के आधार पर सामान्य यात्री बसों के किराए में 75 प्रतिशत तथा डीलक्स बसों के किराए में 30 प्रतिशत की वृद्धि कर नई अधिसूचना जारी की जाए। साथ ही डीजल की

कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव के अनुसार यात्री किराए के स्वतः समायोजन की स्थायी व्यवस्था भी लागू की जाए। महासंघ का कहना है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो इसका असर प्रदेशभर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर पड़ेगा। संगठन ने शासन से यात्रियों और बस संचालकों दोनों के हितों को ध्यान में रखते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान बस संचालक राधाकृष्ण गुप्ता, मोहम्मद अख्तर, पप्पू छाबड़ा, मुकेश गुप्ता, जितेंद्र सिंह, दिनेश गुप्ता, निक्की खान, सतीश गुप्ता, दीपक गुप्ता, इमरान खान, मनीष गुप्ता, विवेक गुप्ता और अभय गुप्ता सहित अन्य बस संचालक मौजूद रहे।

इश्क,शक और कत्ल : नेहरू पार्क में प्रेमिका की हत्या से दहला सूरजपुर

नेहरू पार्क में प्रेमिका की हत्या के बाद बड़ा सवाल,क्या अब सार्वजनिक पार्कों में बढ़ेगी पुलिस की निगरानी?

सूरजपुर के नेहरू पार्क में दिनदहाड़े वारदात,गले पर किए ताबड़तोड़ वार,कुछ घंटों में जंगल से गिरफ्तार हुआ आरोपी,सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

नेहरू पार्क बना हत्या का गवाह, प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

प्रेमिका की हत्या के बाद जंगल में छिपा आरोपी,पुलिस ने घंटों में दबोचा

नेहरू पार्क हत्याकांड के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल,मॉर्निंग वॉक करने वालों में बढ़ी चिंता

नेहरू पार्क में खून से सना प्यार,शक ने छीनी एक और जिंदगी

-संवाददाता-
सूरजपुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सूरजपुर शहर के नेहरू पार्क में रविवार को दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया,प्रेम संबंध में उपजे शक ने एक युवती की जान ले ली, दूसरे युवक से बातचीत करने के संदेह में एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी,घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया,लेकिन पुलिस ने तेजी दिखाते हुए कुछ ही घंटों के भीतर उसे जंगल से गिरफ्तार कर लिया,यह घटना केवल एक प्रेम प्रसंग का दुखद अंत नहीं है, बल्कि रिश्तों में बढ़ती असहिष्णुता,युवाओं में हिंसक मानसिकता और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है, वहीं शहरवासियों के बीच अब यह मांग भी तेज हो गई है कि नेहरू पार्क और आयुष वाटिका जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाए।

नेहरू पार्क में मुलाकात बनी मौत की वजह- जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नेहरू पार्क में रविवार को रितेश राजवाड़े और राधिका राजवाड़े की मुलाकात हुई थी, दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध बताए जा रहे हैं,पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार मुलाकात के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ, बताया जा रहा है कि आरोपी रितेश को शक था कि राधिका किसी अन्य युवक से भी बातचीत करती है,इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई और देखते ही देखते विवाद हिंसक रूप ले बैठा, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पहले दोनों के बीच काफी देर तक बहस होती रही, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा।

कुछ घंटों में पुलिस ने दबोच लिया आरोपी- घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया, पुलिस ने तत्काल जांच शुरू करते हुए पार्क और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले,इसके अलावा घटनास्थल से मिले भौतिक साक्ष्य,प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई,पुलिस की सक्रियता का परिणाम यह रहा कि घटना के कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी रितेश राजवाड़े को जंगल से गिरफ्तार कर लिया गया,प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर प्रेम संबंध और विवाद की बात स्वीकार की है,पुलिस हत्या में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी सहित अन्य साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है।

प्रेम संबंध में शक बना हत्या की वजह-पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी प्रेमिका पर दूसरे युवक से बातचीत करने का शक करता था, इसी शक ने दोनों के रिश्ते में तनाव पैदा कर दिया था,हालांकि पुलिस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि घटना के पीछे केवल आपसी विवाद था या कोई अन्य कारण भी सामने आता है।

सार्वजनिक पार्कों की सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल-इस घटना के बाद शहर के सबसे व्यस्त सार्वजनिक स्थलों में शामिल नेहरू पार्क और आयुष वाटिका की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बहस शुरू हो गई है, प्रतिदिन सुबह और शाम इन पार्कों में बड़ी संख्या में लोग मॉर्निंग वॉक,योग,व्यायाम और परिवार के साथ समय बिताने आते हैं, महिलाओं,बच्चों और बुजुर्गों की भी यहां अच्छी-खासी मौजूदगी रहती है,ऐसे में दिनदहाड़े हुई हत्या ने लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा कर दी है।

गुस्से में निकाला चाकू,गले पर किए कई वार

पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान आरोपी ने अपने पास रखा चाकू निकाला और राधिका पर हमला कर दिया। उसने युवती के गले पर लगातार कई वार किए,अचानक हुए हमले से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई,जान बचाने की कोशिश में राधिका पार्क परिसर में कुछ दूर तक भागी, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण वह वहीं गिर पड़ी,पार्क में मौजूद लोगों ने शोर सुनते ही घटनास्थल की ओर दौड़ लगाई, इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया।

स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

घटना के बाद पार्क में अफरा-तफरी का माहौल बन गया,मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी, गंभीर रूप से घायल युवती को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई, युवती की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

क्या बढ़ेगी पुलिस की निगरानी?

घटना के बाद स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि दोनों पार्कों में नियमित पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जाए,उनका कहना है कि केवल किसी घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी पर्याप्त नहीं है,बल्कि लगातार निगरानी और गश्त की आवश्यकता है,लोगों का कहना है कि पार्कों में शाम के समय कई युवा समूहों की आवाजाही रहती है,ऐसे में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस की नियमित उपस्थिति जरूरी है।

सीसीटीवी की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग...

स्थानीय लोगों ने पार्कों में लगे सीसीटीवी कैमरों की नियमित मॉनिटरिंग, अतिरिक्त कैमरे लगाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा गार्डों की तैनाती की मांग भी की है,उनका कहना है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत होती तो ऐसी घटनाओं की संभावना कम हो सकती थी।

समाज के लिए भी एक चेतावनी

यह घटना केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी गंभीर चेतावनी है,रिश्तों में अविश्वास,संदेह और गुस्से पर नियंत्रण न रख पाने की प्रवृत्ति कई बार अपराध का रूप ले लेती है,विशेषज्ञों का मानना है कि मतभेद या संबंधों में तनाव की स्थिति में हिंसा का रास्ता अपनाने के बजाय संवाद और कानूनी तरीके अपनाना ही उचित विकल्प है।

पुलिस की जांच जारी

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है,साथ ही हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी,फॉरेंसिक साक्ष्य,मोबाइल फोन और अन्य तकनीकी पहलुओं की भी जांच की जा रही है, अब इस पूरे मामले में पुलिस की विस्तृत विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद ही हत्या के सभी कारण पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे,वहीं इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या शहर के सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को अब नए सिरे से मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी दु:खद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

करोड़ की उठाईगिरी के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर मंथन,सर्राफा कारोबारियों में बढ़ी बेचैनी

आरोपियों का सुराग नहीं मिलने से व्यापारियों में नाराजगी,आईजी को सौंपा ज्ञापन, पुलिस ने जिलेभर में बैंक और ज्वेलर्स की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

सीतापुर में दिनदहाड़े करीब एक करोड़ रुपए के सोने-चांदी के जेवरात से भरा बैग पार होने की घटना ने केवल पुलिस ही नहीं,बल्कि पूरे सर्राफा कारोबार को चिंता में डाल दिया है। वारदात के दूसरे दिन भी आरोपियों का कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। घटना के बाद जहां पुलिस की कई टीमें लगातार जांच में जुटी हैं, वहीं सर्राफा कारोबारियों ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई है। रविवार सुबह सीतापुर निवासी अरुण देव सोनी अपनी ज्वेलरी दुकान खोलने पहुंचे थे। स्कूटी में रखा सोने-चांदी के जेवरात से भरा बैग शटर खोलने के दौरान अज्ञात बदमाश लेकर फरार हो गए। दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में एक युवक बैग लेकर जाता दिखाई दिया है। कुछ दूरी पर उसका साथी बाइक के साथ इंतजार कर रहा था। दोनों वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब एक करोड़ रुपए बताई गई है। घटना के बाद पुलिस ने जांच का दायरा तेजी से

बढ़ाया है। साइबर सेल और स्थानीय पुलिस की सात से आठ टीमें अलग-अलग बिंदुओं पर काम कर रही हैं। अब तक करीब 150 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा चुकी है। पुलिस अंतरराज्यीय गिरोहों की गतिविधियों को भी खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ सक्रिय गिरोहों के एंगल पर भी जांच आगे बढ़ाई जा रही है, हालांकि अभी तक किसी की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है।

सर्राफा एसोसिएशन ने आईजी को सौंपा ज्ञापन : इस बीच घटना को लेकर सर्राफा कारोबारियों में नाराजगी बढ़ गई है। सोमवार को छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन (सरगुजा संभाग) और अंबिकापुर सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आईजी दीपक झा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि दिनदहाड़े हुई इतनी बड़ी वारदात ने व्यापारियों का भरोसा डगमगा दिया है। ज्ञापन में पूर्व में रामानुजगंज की सर्राफा चोरी के सफल खुलासे का उल्लेख करते हुए सीतापुर मामले में भी विशेष टीम बनाकर जल्द बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई।

घटना के बाद सरगुजा पुलिस भी पूरी तरह सतर्क हो गई है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देश पर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों ने बैंक, एटीएम, ज्वेलर्स दुकानों और अन्य वित्तीय संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। पुलिस ने संचालकों को उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखने, सुरक्षा गार्ड तैनात करने, आपातकालीन अलार्म सिस्टम लगाने तथा संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक और ज्वेलर्स प्रतिष्ठानों के आसपास गश्त बढ़ाने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग टीमों को विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। सीतापुर की इस वारदात ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बड़ी नकदी और कीमती जेवरों के कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की आवश्यकता है। फिलहाल व्यापारियों की निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं और उन्हें उम्मीद है कि आरोपी जल्द गिरफ्त में होंगे तथा चोरी गए जेवरात बरामद किए जा सकेंगे।

उर्वरकों के अवैध परिवहन पर संयुक्त टीम की कार्रवाई

तीन मीट्रिक टन डीएपी खाद सहित एक पिकअप वाहन जब्त

-संवाददाता-
बलरामपुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

जिले में उर्वरकों के अवैध परिवहन, विक्रय और भण्डारण पर अंकुश लगाने हेतु कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में विकासखंड वाड्रफनगर के ग्राम रघुनाथनगर में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए बिना वैध दस्तावेजों के परिवहन किए जा रहे 60 बोरी (3 मीट्रिक टन) डीएपी खाद के साथ एक पिकअप वाहन को जब्त किया है। कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी एवं उनकी टीम ने ग्राम रघुनाथनगर में एक पिकअप वाहन क्रमांक यूपी 64 टी 3538 का जांच किया। जांच में उक्त पिकअप वाहन में 60 बोरी डीएपी खाद पाया गया। जिस पर चालक अशोक कुमार द्वारा खाद के परिवहन से संबंधित कोई भी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना वैध दस्तावेजों के अवैध रूप से खाद का परिवहन किए जाने की पुष्टि होने पर, रघुनाथनगर थाना प्रभारी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए डीएपी खाद से भरे पिकअप को जब्त किया गया। इस दौरान थाना प्रभारी श्री धीरेंद्र तिवारी, उर्वरक निरीक्षण श्री भूपेश गुप्ता, वरिष्ठ विकास अधिकारी, आरएईओ मौजूद रहे।

कार्य स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए आंतरिक शिकायत समिति

लैंगिक उत्पीड़न पर महिलाएं दर्ज करा सकती हैं शिकायत

-संवाददाता-
बलरामपुर,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

महिलाओं को सुरक्षित, सम्मानजनक एवं भयमुक्त कार्य वातावरण उपलब्ध कराना प्रत्येक संस्थान एवं समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। जिसके लिए महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 लागू किया गया है। जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी संस्थाओं, कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों से अपील की गई है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने आंतरिक शिकायत समिति को क्रियाशील रखें। उन्होंने बताया कि जिस भी कार्यालय, संस्था अथवा प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इस अधिनियम के तहत आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया जाना अनिवार्य है। यदि किसी महिला कर्मचारी के साथ कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की घटना घटित होती है, तो वह निर्धारित समयावधि के भीतर इस समिति के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। समिति शिकायत प्राप्त होने पर निष्पक्ष जांच कर अपनी अनुशंसा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है। ऐसे कार्यस्थल जहां 10 से कम कर्मचारी कार्यरत हों अथवा जहां आंतरिक शिकायत समिति का गठन संभव न हो, वहां पीड़ित महिला जिला स्तर पर गठित स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकती है। घरेलू कार्यकर्ता भी अपनी शिकायत स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष दर्ज करा सकती हैं। समिति शिकायत की गोपनीयता बनाए रखते हुए निष्पक्ष जांच करती है तथा आवश्यक अनुशंसा संबंधित प्राधिकारी को भेजती है।

संत रविदास की 650वीं जयंती को लेकर भाजपा की कार्यशाला आयोजित

सामाजिक समरसता के संदेश के प्रसार और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों पर हुआ मंथन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 जुलाई 2026
(घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी सरगुजा द्वारा स्थानीय राजमोहिनी सभागार में संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती, हर घर तिरंगा अभियान एवं गुरु पूर्णिमा के आयोजन की तैयारियों को लेकर कार्यशाला आयोजित की गई। बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पत्थलगांव विधायक गोमती साय उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी, संभाग प्रभारी अवधेश चंदेल, जिला सह प्रभारी सुनील गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत, बस्तर संभाग सह प्रभारी हरपाल सिंह भामरा तथा जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह शामिल रहे। गोमती साय ने अपने संबोधन में संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और मानवता के संदेश पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने बताया कि वाराणसी से पवित्र माटी एवं जल कलश प्रदेश लाकर विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि जयंती वर्ष के दौरान प्रदेशभर में सामाजिक समरसता यात्राएं, विचार गोष्ठियां, सेवा गतिविधियां, स्वच्छता अभियान तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी संत रविदास के जीवन दर्शन से परिचित हो सके। संभाग प्रभारी अवधेश चंदेल और जिला सह प्रभारी सुनील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं से अभियान को बूथ स्तर तक सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया ने कहा कि जिले के प्रत्येक मंडल और बूथ पर सामाजिक समरसता एवं सेवा आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री विनोद हर्ष ने किया तथा आर.डी. चौहान ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अरुणा सिंह, संतोष दास, विद्यानंद मिश्रा, निश्चल प्रताप सिंह, हरमिंदर सिंह टिन्नी, मधुसूदन शुक्ला, फूलेश्वरी सिंह, मधु चौदाहा, वैभव सिंह देव, जन्मेजय मिश्रा, अजय प्रताप सिंह सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पेयजल संकट, भ्रष्टाचार और ठप विकास कार्यों के खिलाफ

फूटा जनाक्रोश

राजीव गांधी चौक पर गरजा कांग्रेस का धरना

- महिलाओं, व्यापारियों और नागरिकों की बड़ी भागीदारी
- पानी, सफाई, कर्मचारियों के वेतन और ठप विकास कार्यों को लेकर उठाई समस्याएं
- योगेश शुक्ला बोले- 'जनता का हक छीनने वालों को अब जनता ही जवाब देगी'

समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो
होगा उग्र जन आंदोलन: कांग्रेस

नेता प्रतिपक्ष लाल मुनि यादव की अगुवाई में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन

जनसमस्याओं पर कांग्रेस का हल्ला बोल,लाल मुनि यादव की अगुवाई में नगर पालिका के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन

पानी, सफाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन,उग्र आंदोलन की चेतावनी

'अब जनता जवाब देगी' पेयजल संकट और बदहाल व्यवस्था को लेकर नगर पालिका पर बरसी कांग्रेस

पेयजल संकट से ठप विकास तक, जनआक्रोश के बीच नगर पालिका प्रशासन पर साधा निशाना

नगर पालिका की कार्यशैली पर कांग्रेस का हमला,पेयजल और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गरजा जनआंदोलन

-रवि सिंह-

कोरिया/शिवपुर-चरचा,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
नगर पालिका परिषद शिवपुर-चरचा में व्याप्त पेयजल संकट,सफाई व्यवस्था की बदहाली, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने, कथित भ्रष्टाचार तथा पिछले दो वर्षों से विकास कार्यों के ठप पड़े रहने के विरोध में सोमवार को राजीव गांधी चौक जनआक्रोश का केंद्र बन गया,कांग्रेस के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन में नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लाल मुनि यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी,कार्यकर्ता,महिलाएं,व्यापारी,युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। धरना स्थल पर पूरे दिन नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारे गूंजते रहे और जनहित से जुड़े मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई की मांग उठती रही, आंदोलन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नगर पालिका परिषद अपने मूल दायित्वों का निर्वहन करने में असफल साबित हुई है। नगरवासी पानी, सफाई,सड़क,नाली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान हैं,जबकि जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि समस्याओं के समाधान के बजाय केवल आश्वासन देने तक सीमित हैं।

शिवपुर-चरचा में फिर भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर, जनता किसे देगी भरोसा?

शिवपुर-चरचा नगर पालिका का चुनावी इतिहास बताता है कि यहां की जनता ने अब तक भाजपा और कांग्रेस दोनों को लगभग बराबर अवसर दिए हैं,नगर पालिका में दो बार भाजपा ने सत्ता हासिल की है तो दो बार कांग्रेस को भी जनता ने जिम्मेदारी सौंपी है,हालांकि कांग्रेस के दूसरे कार्यकाल के दौरान राजनीतिक परिस्थितियां बदलीं और भाजपा ने सत्ता में सेंध लगाकर समीकरण बदल दिए,ऐसे में आगामी नगर पालिका चुनाव एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी और दिलचस्प टक्कर का संकेत दे रहा है,इस बार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी खोई हुई सत्ता को वापस हासिल करने की होगी, जबकि भाजपा अपने मौजूदा राजनीतिक आधार और सत्ता को बरकरार रखने के लिए पूरा दम लगाएगी। लेकिन दोनों दलों के सामने अपनी-अपनी अलग-अलग चुनौतियां भी मौजूद हैं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल अभी भी नेतृत्व और प्रत्याशी चयन का है, पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाएगी और कौन ऐसा उम्मीदवार होगा जो संगठन और जनता दोनों का विश्वास जीतकर कांग्रेस की नैया पार लगाएगा,यह चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहेगा,इसके साथ ही कांग्रेस के लिए आंतरिक एकजुटता भी बड़ी परीक्षा होगी। यदि पार्टी गुटबाजी से ऊपर उठकर एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरती है, तो भाजपा को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में आ सकती है,लेकिन यदि अंदरूनी मतभेद हावी रहे तो सत्ता वापसी की राह और कठिन हो सकती है, वहीं भाजपा के लिए भी चुनाव आसान नहीं माना जा सकता। लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण इस बार उसके कार्यकाल का मूल्यांकन जनता करेगी, नगर की मूलभूत सुविधाएं,विकास कार्य,पेयजल, सफाई, सड़क,कर्मचारियों की समस्याएं और जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में रहने की संभावना है,ऐसे में भाजपा को केवल संगठन के भरोसे नहीं, बल्कि अपने कार्यकाल के प्रदर्शन के आधार पर भी जनता का विश्वास जीतना होगा,कुल मिलाकर शिवपुर-चरचा नगर पालिका का आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सत्ता बचाने की लड़ाई नहीं होगा,बल्कि यह जनता के विश्वास,विकास के दावों और दोनों प्रमुख दलों की राजनीतिक रणनीति की भी परीक्षा होगी। अब देखना होगा कि जनता एक बार फिर सत्ता परिवर्तन का फैसला करती है या भाजपा को लगातार एक और मौका देती है। चुनावी रण में बाजी आखिर किसके हाथ लगेगी,इसका फैसला नगर की जनता अपने मत से करेगी।

महिलाओं और व्यापारियों की बड़ी भागीदारी बनी आंदोलन की ताकत

धरना-प्रदर्शन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं और व्यापारियों की सक्रिय भागीदारी रही,बड़ी संख्या में महिलाएं हाथों में तख्तियां लेकर धरना स्थल पहुंचीं और नगर की बदहाल व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज बुलंद की,व्यापारियों ने भी नगर की अव्यवस्था और विकास कार्यों में कथित लापरवाही पर चिंता व्यक्त करते हुए आंदोलन का समर्थन किया,आयोजकों ने कहा कि यह केवल कांग्रेस का आंदोलन नहीं,बल्कि नगर की जनता के अधिकारों की लड़ाई है,उन्होंने आंदोलन में शामिल सभी नागरिकों,महिलाओं और व्यापारी वर्ग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की यही एकजुटता बदलाव का आधार बनेगी।

पेयजल संकट से परेशान नगर, बूंद-बूंद पानी के लिए भटक रहे लोग-

धरने में सबसे अधिक चर्चा नगर में गहराते पेयजल संकट को लेकर हुई,वक्ताओं ने आरोप लगाया कि नगर के कई वार्डों में नियमित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो रहा है,कई परिवारों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है,कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह स्थिति किसी भी नगर पालिका के लिए गंभीर चिंता का विषय है,लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं।

लाल मुनि यादव बोले...जनता के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी-धरना को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष लाल मुनि यादव ने नगर पालिका प्रशासन पर तीखा हमला बोला,उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद जनता की अपेक्षाओं पर पूरी तरह विफल साबित हुई है, उन्होंने कहा,लोगों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है,नालियां गंदगी से भरी हुई हैं,कर्मचारी वेतन के लिए परेशान हैं और विकास कार्य पूरी तरह ठप्प पड़े हैं,यदि जनता की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो यह आंदोलन केवल एक दिन के धरने तक सीमित नहीं रहेगा,बल्कि जन-जन को साथ लेकर व्यापक जनआंदोलन चलाया जाएगा।

योगेश शुक्ला बोले...जनता अब आश्वासन नहीं,परिणाम चाहती है-वरिष्ठ कांग्रेसी नेता योगेश शुक्ला ने कहा कि जनता ने विकास और बेहतर व्यवस्थाओं की उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधियों को चुना था, लेकिन आज हालात यह हैं कि नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं,उन्होंने कहा, 'भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी ने विकास की गति रोक दी है, यदि प्रशासन जनता की आवाज को अनसुना करेगा तो कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी,जनता का हक छीनने वालों को अब जनता ही लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देगी।

अशोक जायसवाल बोले...कांग्रेस हमेशा जनता के साथ खड़ी रही-कांग्रेस नेता अशोक जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के सुख-दुख में साथ खड़ी रही है, उन्होंने कहा...'जब-जब जनता पर कोई संकट आया है, कांग्रेस के लोगों ने आवाज उठाई है, आज भी हम नगर की जनता की समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी जनता के बीच रहकर उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। '

वेदांती तिवारी बोले...जनता का सब्र अब टूट चुका है- कांग्रेस नेता वेदांती तिवारी ने कहा कि धरना स्थल पर उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि जनता अब चुप नहीं बैठेगी, उन्होंने कहा, 'लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है,जब जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं तो जनता उन्हें सबक सिखाना जानती है। कांग्रेस हर नागरिक के अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। '

समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन-धरना-प्रदर्शन के समापन पर कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त रूप से चेतावनी दी कि यदि नगर पालिका प्रशासन ने पेयजल संकट, सफाई व्यवस्था, कर्मचारियों के वेतन भुगतान, कथित भ्रष्टाचार और ठप पड़े विकास कार्यों को लेकर शीघ्र ठोस कार्रवाई नहीं की, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा, नेताओं ने कहा कि आगामी दिनों में नगर पालिका का घेराव, जनजागरण अभियान और बड़े स्तर पर जनआंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी, उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस पीछे हटने वाली नहीं है।

ये रहे प्रमुख रूप से मौजूद- धरना-प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष लाल मुनि यादव, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता योगेश शुक्ला, वेदांती तिवारी, दीपक गुप्ता, अजय सिंह, हेम सागर यादव, अनिल जायसवाल, चन्द्रप्रकाश रजवाड़े, सोहेल अहमद, अभिजीत सिंह, राजकुमार पासवान, विजेन्द्र कुमार, गणेश जायसवाल, अशोक जायसवाल, जागृत कुरे, बल्ली मोदी, जानू वशीम, विक्रांत सिंह, गणेश राजवाड़े, संगीता राजवाड़े,रविशंकर राजवाड़े,नीता मिश्रा,एजाज गुड्डू, धर्मवीर यादव, आशीष डबरे, प्रवीण भट्टाचार्य, ईश्वर सिंह पटना,राकेश सिंह पटना, रामाधार टोपो, अनिल सिंह, नौशाद अली, दिनेश यादव,भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता,महिलाएं,व्यापारी एवं नगरवासी उपस्थित रहे।

बारिश में सफाई व्यवस्था ध्वस्त,बीमारियों का खतरा बढ़ा...

धरना-प्रदर्शन में नगर की सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे भी प्रमुखता से उठाए गए, नेताओं ने कहा कि बारिश का मौसम शुरू होने के बावजूद नालियों की सफाई नहीं कराई गई है,कई स्थानों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है,जिससे मच्छरजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है,आरोप लगाया गया कि नगर पालिका द्वारा न तो नियमित रूप से ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जा रहा है और न ही कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जा रहा है, इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बढ़ गई है।

विकास कार्य दो वर्षों से ठप होने का आरोप-

धरना स्थल से वक्ताओं ने नगर पालिका प्रशासन पर विकास कार्यों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया, उनका कहना था कि पिछले लगभग दो वर्षों से नगर में नए विकास कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं और कई स्वीकृत कार्य भी अधूरे पड़े हैं, कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में कथित कमीशनखोरी और अनियमितताओं के कारण नगर का विकास प्रभावित हुआ है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है।

गणेश राजवाड़े ने कहा...माताएं-बहनें पानी के लिए भटक रहीं...

कांग्रेस नेता गणेश राजवाड़े ने कहा कि नगर में पेयजल संकट भयावह रूप ले चुका है,उन्होंने कहा...'माताओं और बहनों को बूंद-बूंद पानी के लिए भटकना पड़ रहा है, प्रशासन कागजों में विकास दिखा रहा है, जबकि जमीन पर स्थिति बिल्कुल अलग है, यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। '

अजय सिंह ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया

कांग्रेस नेता अजय सिंह ने आरोप लगाया कि नगर पालिका में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, उन्होंने कहा...'जो पैसा जनता की सुविधाओं पर खर्च होना चाहिए था, वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। कांग्रेस जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे की बंदरबांट किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। '

भूपेंद्र यादव ने दी घेराव की चेतावनी

कांग्रेस नेता भूपेंद्र यादव ने नगर पालिका प्रशासन पर बरसते हुए कहा कि बारिश शुरू होने के बावजूद नालियों की सफाई और मच्छरों की रोकथाम के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है,उन्होंने कहा...'प्रशासन की यह लापरवाही जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है,यदि तत्काल जनसमस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो कांग्रेस नगर पालिका का घेराव करेगी और व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। '

राम कृष्ण ओझा बने आर्ट ऑफ लिविंग के इंट्यूशन प्रोसेस प्रशिक्षक

बेंगलुरु आश्रम में 11 दिवसीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया, बच्चों की प्रतिभा निखारने वाले विशेष प्रशिक्षण का मिला दायित्व

-संवाददाता-
सूरजपुर,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
नगर के प्रतिष्ठित समाजसेवी, रामायणी, अधिवक्ता एवं कर सलाहकार राम कृष्ण ओझा ने आर्ट ऑफ लिविंग के इंट्यूशन प्रोसेस प्रशिक्षक के रूप में नई उपलब्धि हासिल की है, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित बेंगलुरु आश्रम में आयोजित 11 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण सत्र में सफलतापूर्वक सहभागिता कर यह प्रशिक्षण पूर्ण किया, इस उपलब्धि के साथ अब वे बच्चों के लिए संचालित इंट्यूशन प्रोसेस प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर सकेंगे। उनकी इस सफलता पर सामाजिक, धार्मिक एवं अधिवक्ता वर्ग सहित शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

180 देशों में सक्रिय है आर्ट ऑफ लिविंग-राम कृष्ण ओझा ने

बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग एक विश्वव्यापी संस्था है, जो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में विश्व के लगभग 180 देशों में उच्च मानवीय मूल्यों, तनावमुक्त जीवन और दिव्य समाज निर्माण के उद्देश्य से कार्य कर रही है, संस्था द्वारा विभिन्न आयु वर्ग के लोगों के लिए अनेक प्रकार के व्यक्तित्व विकास और आध्यात्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

शोध के बाद विकसित किया गया इंट्यूशन प्रोसेस- उन्होंने बताया कि वर्षों के शोध और अध्ययन के बाद विकसित किए गए प्रज्ञा योग इंट्यूशन प्रोसेस को विशेष रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है,पिछले दस वर्षों में लाखों बच्चे इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त कर चुके हैं और उनमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं, उनके अनुसार,इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों की एकाग्रता,स्मरण शक्ति, निर्णय क्षमता,आत्मविश्वास,निडरता और सही-गलत की पहचान करने की क्षमता विकसित करने का प्रयास किया जाता है।

अलग-अलग आयु वर्ग के लिए अलग प्रशिक्षण-राम कृष्ण ओझा ने बताया कि इंट्यूशन प्रोसेस के अंतर्गत बच्चों को उनकी आयु के अनुसार अलग-अलग समूहों में प्रशिक्षण दिया जाता है, इसमें 5 से 8 वर्ष, 8 से 13 वर्ष तथा 13 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं,उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान बच्चों की रचनात्मकता और आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

गुरुदेव के प्रति जताया आभार

राम कृष्ण ओझा ने इस उपलब्धि का श्रेय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन को देते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, उन्होंने अपनी मुख्य प्रशिक्षक गरिमा जी,सह प्रशिक्षक प्रज्ञा जी, अन्नामलाई जी, मेहुल जी, मनीष जी एवं प्रियंका जी सहित सभी सहयोगी प्रशिक्षुओं,मित्रों और परिजनों का आभार व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि सभी के मार्गदर्शन,सहयोग और प्रेरणा से ही यह उपलब्धि संभव हो सकी, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से वे क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचकर उनके व्यक्तित्व विकास और आत्मविश्वास बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे।

पीएम मोदी के कदम और सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने पर भाजपा का विपक्ष पर हमला

जिलाध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी बोले...छात्रों के हित में केंद्र सरकार ने उठाए ठोस कदम,विपक्ष का उद्देश्य केवल राजनीति करना था...

-संवाददाता-
सूरजपुर,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।
भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर छात्रों के हित में उठाए गए कदमों तथा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपना अनशन समाप्त किए जाने के बाद कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रमों से विपक्ष की राजनीति उजागर हुई है, भाजपा जिलाध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की पहल की है, उनके अनुसार, सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए

आवश्यक कानूनी प्रावधानों पर भी काम कर रही है।

'छात्रों के भविष्य के लिए सरकार गंभीर'- मुरली मनोहर सोनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार छात्रों और युवाओं के हितों के प्रति संवेदनशील है, उन्होंने दावा किया कि सरकार परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के सकारात्मक रुख के बाद सोनम वांगचुक द्वारा अनशन समाप्त किया जाना इस बात का संकेत है कि संवाद और समाधान की दिशा में प्रयास किए गए।

विपक्ष पर साधा निशाना

भाजपा जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और 'इंडी गठबंधन' के दलों का उद्देश्य समस्या का समाधान करना नहीं, बल्कि इस मुद्दे पर राजनीतिक लाभ लेना था। उन्होंने कहा कि विपक्ष छात्रों के मुद्दों को राजनीतिक रंग देकर देश में भ्रम और असंतोष का माहौल बनाने का प्रयास कर रहा था, उनका कहना था कि जब सरकार ने समस्या के समाधान की दिशा में पहल की, तब विपक्ष के आरोपों की वास्तविकता सामने आ गई।

न सड़क, न मूलभूत सुविधाएं, विकास की बात बेमानी

विकास एवं मूलभूत सुविधाओं से कोसो दूर ग्राम सुक्तरा-सेमरिया

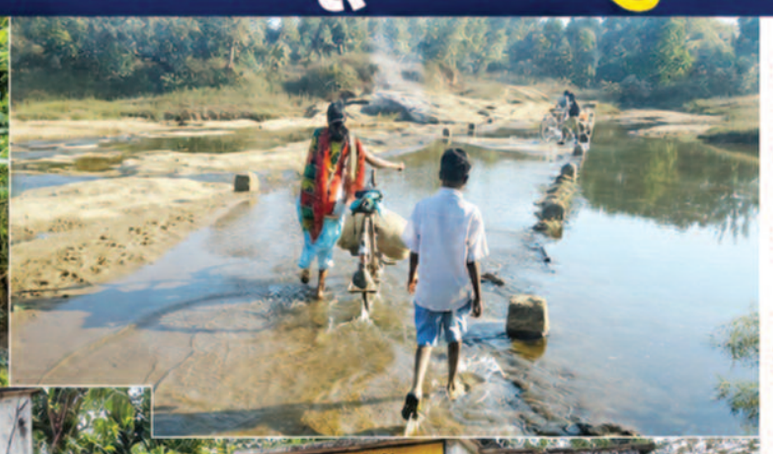

- बिजली नहीं
- सड़क हुई भयावह
- शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल
- हैंडपंप खराब, पीने का पानी समस्या
- सरकारी योजनाएं कागजों तक सीमित
- विकास की बाट जोहते ग्रामवासी

न सड़क, न बिजली, न शुद्ध पेयजल...विकास की राह ताक रहे सुक्तरा-सेमरिया के ग्रामीण

बरसात में कट जाता है संपर्क, ढोंढ़ी का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

सरकारी योजनाओं का इंतजार, बदहाल सड़क और पेयजल संकट से जूझ रहे सुक्तरा-सेमरिया

सड़क नहीं तो विकास नहीं, वनांचल के गांवों में आज भी मूलभूत सुविधाओं का संकट

विकास की बातें बेमानी, जब सड़क-बिजली-पानी के लिए तरस रहे हों ग्रामीण

सोनहत के वनांचल क्षेत्र के कई गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव; बरसात में पगडंडियों के सहारे आवागमन, ग्रामीणों ने सड़क निर्माण और हैंडपंप सुधार की उठाई मांग

20 साल बाद भी नहीं बदली तस्वीर,सड़क,बिजली और पानी को तरसते वनांचल के गांव

राजन पाण्डेय

कोरिया/सोनहत,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

प्रदेश और केंद्र सरकार ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली,पेयजल,शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के दावे करती हैं, लेकिन विकासखंड सोनहत के वनांचल क्षेत्र में बसे ग्राम सुक्तरा,सेमरिया,सलगवां,कुर्थी, ललमट्ठा, रेवला और मझगवां जैसे गांव इन दावों की हकीकत बयां करते नजर आते हैं, आज भी इन गांवों के लोग सड़क,बिजली, शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बरसात के मौसम में हालात और भी भयावह हो जाते हैं,जब सड़कें दलदल में बदल जाती हैं और गांवों का संपर्क लगभग टूट जाता है, ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मांग करने के बावजूद वर्षों से हालात में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। सरकारें बदलीं,पंचायतों के प्रतिनिधि बदले, लेकिन गांवों की तस्वीर नहीं बदली।

20 वर्षों से विकास की बाट जोह रहे ग्रामीण-सेमरिया निवासी अवध यादव, चैनसाय,सुंदरसाय सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पिछले लगभग दो दशकों से गांवों में मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जस की तस बनी हुई है, कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क, बिजली और पेयजल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्य नहीं हो सका,ग्रामीणों का कहना है कि विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित दिखाई देते हैं,जबकि जमीनी स्तर पर लोगों को आज भी कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करना पड़ रहा है।

बिजली और पेयजल की समस्या बनी बड़ी चुनौती-वनांचल क्षेत्र के कई गांवों में बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है, वहीं पेयजल संकट भी गहराता जा रहा है, कई हैंडपंप महीनों से खराब पड़े हैं,जबकि कई स्थानों पर नलकूपों से लाल रंग का पानी निकल रहा है, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा,स्थिति यह है कि कई परिवार आज भी प्राकृतिक जल स्रोतों और ढोंढ़ी के पानी पर निर्भर हैं,ग्रामीणों ने प्रशासन से खराब नलकूपों की मरम्मत और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है।

मनरेगा में काम की मांग-ग्रामीणों ने रोजगार के मुद्दे को भी उठाया,उनका कहना है कि मनरेगा के तहत नियमित कार्य उपलब्ध कराया जाए ताकि लोगों को गांव में ही रोजगार मिल सके और आजीविका का साधन मजबूत हो।

नई पंचायत बनने के बाद भी नहीं बदले हालात-पहले सुक्तरा और सेमरिया ग्राम पंचायत उग्यांव के अंतर्गत आते थे,बाद में अमृतपुर को नई ग्राम पंचायत बनाकर इन गांवों को उससे जोड़ दिया गया, पंचायत मुख्यालय की दूरी तो कुछ कम हुई, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इससे विकास कार्यों की गति में कोई विशेष बदलाव नहीं आया,अधिकांश समस्याएं आज भी पहले जैसी बनी हुई हैं।

क्या कहते हैं जिम्मेदार और सामाजिक प्रतिनिधि-अवध यादव (सामाजिक कार्यकर्ता) ने कहा कि सेमरिया-अमृतपुर मार्ग की स्थिति बेहद खराब है। आए दिन लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उन्होंने घाट कटिंग और सीसी सड़क निर्माण की मांग की।

पुष्पेंद्र राजवाड़े (अध्यक्ष, कोरिया जन सहयोग समिति) ने कहा कि पिछले कार्यकाल में आनंदपुर-नटवाही क्षेत्र में सड़क और पुलिया का निर्माण हुआ, लेकिन सेमरिया क्षेत्र उपेक्षित रह गया, अब यहां सड़क निर्माण प्राथमिकता होना चाहिए।

प्रकाश चंद्र साहू (अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस) ने कहा कि सेमरिया और सुक्तरा में सड़क, घाट कटिंग और सीसी सड़क निर्माण की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जाएगा।

प्रेमसागर तिवारी (अध्यक्ष, पंच संघ) ने बताया कि पंच संघ का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर से मिलकर सेमरिया-अमृतपुर और अमृतपुर-सुक्तरा सड़क निर्माण की मांग करेगा।

बरसात में भयावह हो जाता है सेमरिया पहुंच मार्ग-

वनांचल क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या सड़क है, सोनहत मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम सेमरिया तक पहुंचने वाला मार्ग बरसात में बेहद खतरनाक हो जाता है। लंबी चढ़ाई, उबड़-खाबड़ रास्ता और कीचड़ के कारण दोपहिया वाहन चलाना भी जोखिम भरा हो जाता है, ग्रामीणों के अनुसार आए दिन लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं, कई स्थानों पर पुल-पुलिया नहीं होने से चारपहिया वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाते, आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल ले जाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है, हालात ऐसे हैं कि बरसात के दौरान लोग मुख्य सड़क छोड़कर पगडंडियों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं।

सुक्तरा की सड़क भी बदहाल, ग्रामीणों की उम्मीदें अधूरी-

सिर्फ सेमरिया ही नहीं, बल्कि सुक्तरा गांव की सड़क की स्थिति भी बेहद खराब है, ग्रामीण बताते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान सुक्तरा से अमृतपुर तक अस्थायी मिट्टी सड़क बनाई गई थी, जो शुरुआती कुछ वर्षों तक उपयोगी रही, लेकिन लगातार बारिश के कारण सड़क धीरे-धीरे बहती गई और अब उसकी हालत पहले से भी अधिक खराब हो चुकी है, नई सरकार से क्षेत्रवासियों को सड़क, बिजली और सौर ऊर्जा जैसी सुविधाओं के विस्तार की उम्मीद थी, लेकिन अब तक कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा।

शिक्षा और आंगनबाड़ी व्यवस्था भी प्रभावित-

सड़क और भवनों की खराब स्थिति का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ रहा है, क्षेत्र के कई स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर भवनों में संचालित हो रहे हैं, बरसात के कारण गांवों की गलियां और रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं, जिससे छोटे बच्चों को स्कूल और आंगनबाड़ी तक पहुंचने में भारी परेशानी होती है, ग्रामीणों का कहना है कि इससे बच्चों की उपस्थिति भी प्रभावित हो रही है, कई आंगनबाड़ी केंद्रों में भवन और पोषण आहार जैसी व्यवस्थाओं को लेकर भी शिकायतें सामने आ रही हैं।

स्वास्थ्य सुविधाएं भी सीमित-

स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, हालांकि हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक शिविर आयोजित किया गया था, लेकिन नेटवर्क की समस्या और संसाधनों के अभाव में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं, ग्रामीणों का कहना है कि गंभीर मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि सड़क और संचार व्यवस्था दोनों कमजोर हैं।

विकास के दावों के बीच बड़ा सवाल

वनांचल क्षेत्र के इन गांवों की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है,जब सरकारें हर गांव तक सड़क,बिजली,पानी,शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रही हैं, तब सुक्तरा,सेमरिया और आसपास के गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? बरसात में संपर्क टूटने, खराब पेयजल,जर्जर सड़क और सीमित स्वास्थ्य सेवाओं के बीच ग्रामीणों को अब भी उस विकास का इंतजार है, जिसकी घोषणाएं वर्षों से होती रही हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इन समस्याओं के समाधान के लिए कब तक ठोस कदम उठाते हैं।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने आईएलएस अस्पताल पहुंचकर एमसीबी जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष के पिता का जाना हालचाल

चिकित्सकों से ली स्वास्थ्य की जानकारी,बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के दिए निर्देश,शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की...

-संवाददाता-
रायपुर/एमसीबी,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित आईएलएस अस्पताल पहुंचकर मनेंद्रगढ़-झगराखंड निवासी एवं एमसीबी जिला प्रेस क्लब के अध्यक्ष रंजीत सिंह के पूज्य पिता शंकर सिंह का हालचाल जाना,इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए,इससे पूर्व भरतपुर-सोनहत के पूर्व विधायक गुलाब कमरो भी आईएलएस अस्पताल पहुंचकर शंकर सिंह से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जान चुके थे,उन्होंने भी परिवारजनों से चर्चा कर उपचार की जानकारी ली और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

चिकित्सकों से ली उपचार की विस्तृत जानकारी-स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों से शंकर सिंह की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति,चल रहे उपचार और आगे की चिकित्सा प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी ली,उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि मरीज के उपचार में किसी प्रकार की कमी न रहे और आवश्यकतानुसार सभी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

परिजनों को दिया ढांढस-अस्पताल में मंत्री ने रंजीत सिंह एवं अन्य परिजनों से भी मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया,उन्होंने कहा कि शासन की ओर से उपचार के संबंध में हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा,साथ ही चिकित्सकों पर विश्वास बनाए रखने की बात कहते हुए उन्होंने शंकर सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने भी की कुशलक्षेम की जानकारी-पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने अस्पताल पहुंचकर शंकर सिंह का हालचाल जानने के साथ परिजनों से मुलाकात की, उन्होंने चिकित्सकों से उपचार की जानकारी प्राप्त करते हुए आशा व्यक्त की कि उचित चिकित्सा से वे शीघ्र स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे।

शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना-स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और पूर्व विधायक गुलाब कमरो ने शंकर सिंह के शीघ्र पूर्ण स्वस्थ होने एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना की,उन्होंने कहा कि सभी की शुभकामनाएं और चिकित्सकों का समुचित उपचार उन्हें जल्द स्वस्थ होने में सहायक सिद्ध होगा।

हर घर तिरंगा अभियान और संत गुरु रविदास जयंती की तैयारियों को लेकर भाजपा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न

11 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान...मंडलों और गांवों में निकलेगी तिरंगा यात्रा, संत गुरु रविदास के समरसता संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर,27 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय छिंदडांड़,बैकुण्ठपुर में सोमवार को हर घर तिरंगा अभियान तथा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के आयोजन को लेकर जिला स्तरीय बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया,बैठक में आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई तथा पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं,बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक भईयालाल राजवाड़े उपस्थित रहे,उनके साथ प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष मोहित पैकरा,जिला उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल,राजेश सिंह, अनिल जायसवाल,जिला महामंत्री पंकज गुप्ता,कपिल जायसवाल,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शैलेष शिवहरे,नगर पंचायत अध्यक्ष गायत्री सिंह,जनपद उपाध्यक्ष प्यारे साहू, जिला मंत्री प्रदीप तिवारी,सुनीता कुर्रे,शारदा गुप्ता,जिला मीडिया प्रभारी तीरथ राजवाड़े सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे।

11 से 15 अगस्त तक चलेगा हर घर तिरंगा अभियान

बैठक को संबोधित करते हुए विधायक भईयालाल राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 11 से 15 अगस्त तक जिलेभर में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा अभियान व्यापक जनभागीदारी के साथ चलाया जाएगा,उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस अभियान को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेगा ताकि अधिक से अधिक लोग राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ें।

संत गुरु रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान

विधायक राजवाड़े ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज ने समरसता,समानता और मानवता का संदेश दिया था,उनकी 650वीं जयंती के अवसर पर जिले और मंडल स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे,उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने वाले उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं और उन्हें जन-जन तक पहुंचाना सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है।

13 से 15 अगस्त तक हर घर और प्रतिष्ठानों पर फहराया जाएगा तिरंगा-

प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्णबिहारी जायसवाल ने कहा कि देशभर में करोड़ों कार्यकर्ता देशवासियों के साथ मिलकर 13 से 15 अगस्त तक प्रत्येक घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने के अभियान में भाग लेंगे,उन्होंने विशेष रूप से बच्चों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि इससे नई पीढ़ी में राष्ट्रभक्ति,एकता और अखंडता की भावना मजबूत होगी।

10 से 14 अगस्त तक निकलेगी भव्य तिरंगा यात्रा-

जिला महामंत्री पंकज गुप्ता ने बताया कि जिले के प्रत्येक मंडल मुख्यालय के साथ-साथ मंडल के पांच प्रमुख गांवों और बाजारों में 10 से 14 अगस्त के बीच भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, उन्होंने कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों से अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

वीर सैनिकों और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों का होगा सम्मान-

बैठक में निर्णय लिया गया कि अभियान के दौरान प्रत्येक मंडल में भारत माता के वीर सपूत सैनिकों तथा देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले पुलिसकर्मियों के परिजनों के घर जाकर उनका सम्मान किया जाएगा, पार्टी नेताओं ने इसे राष्ट्रसेवा के प्रति सम्मान प्रकट करने का महत्वपूर्ण प्रयास बताया।

बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री कपिल जायसवाल ने किया,बैठक में जिला कार्यालय मंत्री मंजू जिवनानी,सह कार्यालय मंत्री मनोज साहू, जिला सह मीडिया प्रभारी वर्षा साहू, गणेश यादव,जिला सोशल मीडिया प्रभारी जगनारायण साहू,पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष कुन्ती चक्रधारी,मंडल अध्यक्ष रामलखन यादव, मनेजर राजवाड़े,दीपा विश्वकर्मा, राजाराम राजवाड़े,संजय चिकनजूरी,रमन गुप्ता,रवि त्रिपाठी,मुन्नाराम चक्रधारी,सचिन मलिक,सच्चिदानंद द्विवेदी,सुरेश सिरदार, सुरेश राजवाड़े, बालकृष्ण देवांगन, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष रीता यादव,महामंत्री पुष्पलता राजवाड़े, युवा मोर्चा जिला महामंत्री साक्षी सिंह राजपूत, अनुसूचित जाति मोर्चा जिलाध्यक्ष दिलराज रवि,महामंत्री लहरे सोनवानी, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष शिवचरण साहू, महामंत्री जय चक्रधारी, चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक अनिता गुप्ता, शिक्षा प्रकोष्ठ जिला संयोजक गोकरण शुक्ला, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुखदेव राजवाड़े, एनजीओ प्रकोष्ठ जिला संयोजक योगेंद्र मिश्रा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कुसुम जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

CMYK

50 हफ्ते नॉन-स्टॉप सिनेमाघरों में चली थी अनिल कपूर की ये ब्लॉकबस्टर फिल्म

कभी गोविंदा को भी ऑफर हुई थी मूवी

38 साल पहले अनिल कपूर ने अपने करियर की सबसे बड़ी हिट दी थी। इस फिल्म ने 50 हफ्ते तक बड़े पर्दे पर राज किया था। 38 साल पहले अनिल कपूर एक ऐसी फिल्म लेकर आए थे जिसने उनका करियर ही चमका दिया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी।अनिल कपूर की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने 1988 में आई ब्लॉकबस्टर मूवीज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था और खुद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। इतना ही नहीं, यह फिल्म उस साल की गोल्डन जुबली भी बन गई।

गोल्डन जुबली रही थी फिल्म

जब अनिल कपूर एंग्री यंग मैन बनकर बड़े पर्दे पर आए थे तब सिनेमाघरों सीटियों से गूंज गया था। एक-दो हफ्ते नहीं, बल्कि 50 हफ्तों तक यह फिल्म देखने के लिए दर्शक सिनेमाघरों में आते रहे।

माधुरी दीक्षित के लिए था बड़ा ब्रेक

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं,वो है तेजाब । इस फिल्म का निर्देशन एन. चंद्रा ने किया था। यह माधुरी दीक्षित के करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी और अनिल कपूर की सफलता को नई ऊंचाइयां मिली थीं।

50 हफ्तों तक थिएटर्स में किया था राज

तेजाब 1988 की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बन गई थी। 50 हफ्तों से ज्यादा चलने वाली ये फिल्म गोल्डन जुबली बन गई। अनिल कपूर की तेजाब ने इसी साल सिनेमाघरों में आईं अमिताभ बच्चन की शहंशाह और आमिर खान की कयामत से कयामत तक फिल्मों को पछाड़ दिया था।

गोविंदा को ऑफर हुई थी मूवी

इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ सपोर्टिंग रोल में चंकी पांडे नजर आए थे। मगर पहले यह रोल गोविंदा को ऑफर हुई थी। हालांकि, डेट इश्यू की वजह से गोविंदा यह फिल्म नहीं कर पाए और बब्बन के किरदार में चंकी छा गए। आज यह फिल्म कल्ट क्लासिक में गिना जाता है। इसके सारे गाने भी हिट हुए थे जिसमें से एक एक दो तीन चार पांच कल्ट क्लासिक बन गया।

फिल्म की स्टार कास्ट

एन चंद्रा की तेजाब में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित,मंदाकिनी,अनुपम खेर, किरण कुमार,चंकी पांडे,अरुणा ईरानी और अन्नू कपूर अहम भूमिकाओं में हैं।

प्रभास की स्पिरिट में कैटरीना कैफ की एंट्री?

2 साल बाद एक्ट्रेस की बड़े पर्दे पर होगी वापसी?

साउथ सुपरस्टार प्रभास की आने वाली फिल्म स्पिरिट इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ महीने पहले ही दीपिका पादुकोण इस फिल्म से बाहर हो चुकी हैं, जिसके बाद फिल्म में तृप्ति डिमरी और प्रभास की जोड़ी देखने को मिलेगी। इसी बीच फिल्म से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं,जो फैंस के बीच चर्चा में है।रिपोर्ट के अनुसार,फिल्म के मेकर्स कैटरीना कैफ से कैमियो के लिए बात कर रहे हैं। फिल्म में उनका स्क्रीन टाइम कम हो सकता है,लेकिन वह एक मजबूत किरदार में दिखाई देंगी। अगर कैटरीना फिल्म में नजर आती हैं, तो यह उनके फैंस के लिए बहुत खास होने वाला है। शादी के बाद बड़े पर्दे पर वह बहुत कम दिखाई दी हैं और उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाईं। इसीलिए स्पिरिट उनकी बड़ी फिल्मों में से एक हो सकती है। हालांकि, कैटरीना या मेकर्स ने इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।

बता दें कि संदीप रेड्डी वांगा द्वारा निर्देशित इस फिल्म में पहले दीपिका पादुकोण लीड रोल में नजर आने वाली थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक,उन्होंने मेकर्स से 8 घंटे की शिफ्ट, 25 करोड़ रुपये फीस के अलावा फिल्म के प्रॉफिट में 10 प्रतिशत की मांग की थी। इसी वजह से मेकर्स और उनके बीच बात नहीं बनी और उन्होंने फिल्म से किनारा कर लिया। इसके बाद तृप्ति डिमरी को फिल्म के लिए चुना गया,जो दीपिका से कम फीस ले रही हैं।

वहीं कैटरीना की बात करें, तो उन्होंने करीब 20 साल पहले तेलुगु फिल्म मल्लीस्वरी में वेंकटेश और अल्लरी पिडुगु में नंदमूरी बालकृष्ण के साथ काम किया था। बाद में वह बॉलीवुड फिल्मों में सक्रिय रहीं और आखिरी बार उन्हें 2024 में फिल्म मेरी क्रिसमस में विजय सेतुपति के साथ देखा गया था।

अजय देवगन की दृश्यम 3 को टक्कर देगी फैमिली ड्रामा

अभिनेता अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म को साउथ सुपस्टार दग्गुबाती वेंकटेश की नई फिल्म से कड़ी टक्कर मिलेगी। संक्रांति वास्तुनाम की अपार सफलता के बाद अब साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दग्गुबाती वेंकटेश बड़े पर्दे पर वापसी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनकी अपकमिंग फिल्म का नाम आदर्श कुटुंबम- हाउस नंबर 47 है।
इस फिल्म का पहला टीजर सामने आ गया है,साथ ही मेकर्स की तरफ से फिल्म की रिलीज डेट का एलान भी किया गया है, जिससे कहीं न कहीं बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन की बहुचर्चित फिल्म दृश्यम 3 की टेंशन बढ़ सकती है।

आदर्श कुटुंबम का टीजर आउट

दग्गुबाती वेंकटेश की आदर्श कुटुंबम का डायरेक्सन त्रिविक्रम श्रीनिवास ने किया है, जो बतौर फिल्ममेकर सुपरस्टार महेश बाबू और श्रीलीला स्टारर गुंटूर कारूम की असफलता के 2 साल बाद वापसी कर रहे हैं। आदर्श कुटुंबम में वेंकटेश के अलावा केजीएफ फिल्म फेम अदाकारा श्रीनिधी शेट्टी भी अहम भूमिका में मौजूद हैं। उनकी झलक आपको फिल्म के टीजर में देखने को मिल जाएगी। अभिनेता वेंकटेश ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर आदर्श कुटुंबम का टीजर शेयर किया है और फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर है। हालांकि, मेकर्स इसे आदर्श कुटुंबम का फर्स्ट लुक बता रहे हैं, जिसे देखकर ये अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि आदर्श कुटुंबम एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म है।
आदर्श कुटुंबम का टीजर देखने के बाद फैंस की एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गई है और वे इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं।

दृश्यम 3 से होगा क्लैश

बात की जाए दग्गुबाती वेंकटेश की अपकमिंग फिल्म आदर्श कुटुंबम की रिलीज डेट के बारे में तो 2 अक्टूबर 2026 को इस मूवी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 के साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि दृश्यम 3 भी 2 अक्टूबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी।

डी55 के शीर्षक से उठा पर्दा, धनुष और राजकुमार पेरियासामी की फिल्म ओम : चैप्टर 1 से पोस्टर भी जारी

नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले धनुष की डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी के साथ 55वीं फिल्म का ऑफिशियल टाइटल तमिल में ओमः चैप्टर 1 और तेलुगु में ओमः फर्स्ट स्ट्राइक रखा गया है। आर टेक स्टूडियोज और वंडरबार फिल्म्स मिलकर इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और यह उनका पहला साथ में किया गया प्रोजेक्ट है। हाल ही में कास्ट, क्रू और मीडिया की मौजूदगी में इसका टाइटल लॉन्च किया गया।

अमरन की पैन-इंडिया सफलता के बाद, राजकुमार पेरियासामी इस बड़े बजट वाले एक्शन ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म का पहला शेड्यूल पूरा हो चुका है। टीम ने कन्फर्म किया है कि सिनेमैटोग्राफर एझिलारसु,अमरन और करुप्पु के एडिटर कलाईवानन और म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर टेक्निकल क्रू का हिस्सा हैं।

मेकर्स ने पोस्टर के बजाय एक खास वीडियो के ज़रिए धनुष के किरदार को दिखाते हुए ओम का खुलासा किया। डायरेक्टर राजकुमार ने कहा कि इस टाइटल के स्पिरिचुअलिटी (आध्यात्मिकता) से परे कई गहरे मतलब हैं। फिल्म के रिलीज होने से पहले आने वाले महीनों में लीड किरदारों के टीज़र और ट्रेलर जारी किए जाएंगे।

ओम में धनुष, साई पल्लवी, श्रीलीला और मलयालम सुपरस्टार ममूटी (एक अहम रोल में) जैसे कई बड़े कलाकार शामिल हैं। इंडस्ट्री में चर्चा है कि यह तमिल सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक होगी। वंडरबार और आर टेक स्टूडियो को फिल्म के बड़े स्केल और कहानी पर बहुत भरोसा है।

डिवो म्यूज़िक और वार्नर म्यूज़िक इंडिया इसके ऑडियो का काम संभालेंगे। अमरन के साथ राजकुमार की सफलता को देखते हुए, इस फिल्म से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। ओमः चैप्टर 1 को 16 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा और यह पहले से ही उस साल की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई है।

मंदाकिनी का वो गाना,जो बना पहाड़ों की पहचान,दिल को सुकून देता है पुराना लव सॉन्ग

मंदाकिनी हिंदी सिनेमा की वह खूबसूरत अदाकारा रहीं, जो अपने जमने में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल और फिल्ममेकर्स की बतौर एक्ट्रेस पहली पसंद मानी जाती थीं। मंदाकिनी के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली रही, जिसमें वह अभिनेता राजीव कपूर संग नजर आई थीं। राम तेरी गंगा मैली एक लव स्टोरी ड्रामा फिल्म थी,जिसके सारे गाने अपने आप में कल्ट रहे। लेकिन एक गीत ऐसा भी रहा,जो पहाड़ों की पहचान माना जाता है। आइए जानते हैं कि यहां कौन से गीत के बारे में जिक्र किया जा रहा है। मंदाकिनी का कल्ट लव सॉन्ग निर्देशक राज कपूर के फिल्ममेकिंग करियर की सबसे बेहतरीन मूवीज की जब भी बात की जाएगी तो उसमें राम तेरी गंगा मैली का नाम जरूर शामिल होगा। साल 1985 में रिलीज होने वाली इस मूवी में मंदाकिनी पर एक गीत फिल्माया गया था,जो खूबसूरत वादियों और झरनों के बीच रहा। इस गाने के बोल थे- हुस्न पहाड़ों का... ।

खेल समाचार

भारत की शेरनी ज्ञानेश्वरी यादव ने भारत की झोली में डाला एक और सिल्वर

ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किग्रा वर्ग में कुल 199 किग्रा वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया...

लास्गो,27 जुलाई 2026। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय वेटलिफ्टरों का शानदार प्रदर्शन जारी है। महिला 53 किलोग्राम वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत की ज्ञानेश्वरी यादव ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया। चालू राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का वेटलिफ्टिंग में यह चौथा पदक है जिससे भारतीय खेमे में जश्न का माहौल है।

ज्ञानेश्वरी ने जीता एक और मेडल

ज्ञानेश्वरी से पहले भी भारतीय भारोत्तोलकों ने पोडियम पर अपनी जगह पक्की की थी। भारत के लिए स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में स्वर्णिम सफलता हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता था। वहीं पुरुषों के वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला, जहां ऋषिकांत सिंह (60 किग्रा) और मुथुपंडी राजा (65 किग्रा) ने अपने-अपने वर्गों में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था।
वेटलिफ्टिंग के मुकाबलों में खिलाड़ियों को अपनी ताकत और तकनीक का प्रदर्शन दो अलग-अलग चरणों स्नैच और क्लीन एंड जर्क में करना होता है। स्नैच में एथलीट बारबेल को चौड़ी ग्रिप से पकड़कर एक ही झटके में सिर के ऊपर उठाता है। वहीं क्लीन एंड जर्क में पहले वजन को छाती तक लाया जाता है और फिर थोड़ा रुककर पूरे जोर के साथ कोहनियों को सीधा करते हुए सिर के ऊपर स्थिर रखा जाता है। रेफरी का बीप बजने तक खिलाड़ी को उस वजन को संभालकर रखना अनिवार्य होता है।

नाइजीरिया की वेटलिफ्टर ने जीता गोल्ड

फाइनल मुकाबले के स्नैच राउंड में ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम का सफल लिफ्ट किया। स्नैच राउंड की समाप्ति के बाद प्रतिस्पर्धा काफी दिलचस्प हो गई थी,जहां नाइजीरिया की दीदीह 93 किग्रा के साथ पहले स्थान पर थीं, ज्ञानेश्वरी 88 किग्रा के साथ दूसरे नंबर पर बनी हुई थीं,जबकि कनाडा की ग्रूक्स 83 किग्रा उठाकर तीसरे पायदान पर चल रही थीं।

क्लीन एंड जर्क में उठाया 111 किलोग्राम

क्लीन एंड जर्क राउंड में भारतीय लिफ्टर ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए 111 किलोग्राम का शानदार लिफ्ट दर्ज किया। हालांकि,स्वर्ण पदक की रेस में आगे चल रही दीदीह ने 113 किग्रा का वजन उठाकर अपनी बढ़त को बरकरार रखा और गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इस तरह ज्ञानेश्वरी यादव को उपविजेता रहते हुए सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, लेकिन उनके इस प्रदर्शन ने भारत के मेडल तालिका को और मजबूती दे दी है।

पाकिस्तान को फाइनल में रौंदकर भारत बना चैंपियन

मस्कट ,27 जुलाई 2026। ओमान के मस्कट में खेले गए एफआईएच यूथ हॉकी5 एशियन चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय सब-जूनियर पुरुष टीम का जबरदस्त जलवा देखने को मिला है। खिताबी भिड़ंत में टीम इंडिया ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 3-1 के अंतर से धूल चटाकर शानदार अंदाज में ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय टीम एलीट पूल टेबल पर शीर्ष पर रहते हुए फिनिश करने में कामयाब रही। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों टीमों ने आगामी एफआईएच यूथ हॉकी5 वर्ल्ड कप के लिए भी अपनी जगह पक्की कर ली है। टूर्नामेंट में भारतीय टीम का दबदबा शुरुआत से ही देखने को मिला था। लीग चरण के मैच में भी भारत ने पाकिस्तान को 7-3 से करारी शिकस्त दी।

कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर,सरगुजा,छ0ग0

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव गौरव उत्सव स्वर्णिम संकल्प

क्रमांक / 2876/स्टोर/2026 अम्बिकापुर दिनांक,25/07/26

ई-प्रोक्यूरमेंट सिस्टम निविदा आमंत्रण सूचना

राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) की ओर से वाहन स्टैण्ड संचालन के निविदा हेतु फर्मों/अभिकरणों से राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.) में वाहन स्टैण्ड संचालन हेतु ऑनलाईन निविदा निम्नानुसार आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी हेतु वेबसाईट https://eproc.cgstate.gov.in में देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा का नाम	सी.जी.ई. प्रोक्यो निविदा क्रमांक	ऑनलाईन जमा करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय	ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	भौतिक रूप से जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खुलने की तिथि एवं समय
1	शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर में वाहन स्टैण्ड का संचालन	196141	01.08.2026, 10:00 AM	10.08.2026, 04:00 PM	10.08.2026, 05:00 PM	11.08.2026, 12:00 PM

स्थान - कार्यालय,संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा (छ.ग.)

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव,
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय,
अम्बिकापुर सरगुजा (छ0ग0)

जी0नं0 -262702384/2

न्यायालय नायब तहसीलदार दरिमा ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

रा.प्र.क्र./ब-121/2025-26

ईश्तहार

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है आवेदक/आवेदिका केली बाई पति स्व दादू एक्का निवासी ग्राम सोनबरसा के द्वारा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के धारा 13 (3) एवं छ0ग0 मृत्यु रजि0 नियम 2001, के नियम 09 (3) के अन्तर्गत अपने पति स्व0 दादू एक्का पिता स्व0 लक्षण एक्का का मृत्यु दिनांक 13/01/2025 को ग्राम सोनबरसा में होना बतलाते हुये उनके मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदाय बावत आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 15/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

नायब तहसीलदार
दरिमा,सरगुजा

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0-/अ-27/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रंजित विश्वास आ. स्व. पुलिन विश्वास, निवासी ग्राम सुभाषनगर,तहसील अम्बिकापुर,जिला सरगुजा छ.ग.के द्वारा अपने जीवनकाल में अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम सुभाषनगर स्थित खसरा नंबर 62 / 2,60/2,66 / 1 रकबा क्रमशः 1.040, 1.090 हे. में से 20 डिसमिल भूमि अपने पास रखते हुए पुत्री क्रमशः विशाखा मण्डल, सुनीता हालदार, अंजना मिस्त्री को 20-20 डिसमिल भूमि एवं शेष बची भूमि को पुत्र क्रमशः रतन विश्वास, मदन विश्वास, रमेश विश्वास, रनेश विश्वास, परेश विश्वास को बराबर-बराबर अंश में प्रदान करते हुये खाता विभाजन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 15/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

सील

न्यायालय तहसीलदार
अंबिकापुर
जिला-सरगुजा (छ.ग.)

गांवों के समग्र विकास से ही विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प होगा साकार : मुख्यमंत्री साय

रायपुर,27 जुलाई 2026। ग्राम पंचायतों को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। यदि ग्राम पंचायतें सशक्त हों, गांव आत्मनिर्भर बनें और प्रत्येक ग्रामीण विकास की प्रक्रिया का सहभागी बने, तभी विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प वास्तविक रूप ले सकेगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित एसआईआरडी परिसर, निमोरा में आयोजित प्रदेश के सभी जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन का वास्तविक अर्थ यही है कि शासन की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ग्राम पंचायतें जनभागीदारी के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाने का सबसे प्रभावी मंच हैं। अधिकारियों को संवेदनशीलता, ईमानदारी और सेवा भाव के साथ कार्य करते हुए ग्रामीणों का विश्वास जीतना होगा। मुख्यमंत्री साय ने अधिकारियों से कहा कि शासकीय योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और गांव का प्रत्येक नागरिक स्वयं विकास यात्रा का सक्रिय भागीदार बने। उन्होंने प्रत्येक जिले में ऐसे गांवों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां जनभागीदारी, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रभावी योजना के माध्यम से आदर्श विकास मॉडल विकसित किए जा सकें।

विकसित भारत जी राम जी योजना से ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 1 जुलाई से लागू विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने वाली महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना के माध्यम से रोजगार सृजन के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना का निर्माण प्राथमिकता से किया जाए। इसके माध्यम से जल संरक्षण,कृषि, ग्रामीण अधोसंरचना,आजीविका और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर प्रबंधन बने प्राथमिकता : मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं होना चाहिए। जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य, कृषि उत्पादकता, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग ही स्थायी विकास का आधार है। उन्होंने प्रत्येक जिले में स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जल संरक्षण की कार्ययोजना तैयार करने तथा वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

10.40 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति दीदी,अब लक्ष्य करोड़पति दीदी : मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिली है। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब सरकार उन्हें उद्यमिता, कौशल विकास और स्वरोजगार से जोड़कर बड़ी संख्या में करोड़पति दीदी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र महिलाओं की पहचान कर उन्हें स्व-सहायता समूहों,कौशल विकास,आजीविका गतिविधियों और नई औद्योगिक नीति से उत्पन्न अवसरों से जोड़ा जाए।

बस्तर के अंतिम गांव तक पहुंचे विकास की रोशनी : मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बस्तर संभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में विकास कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किए जाएं। उन्होंने कहा कि जिन गांवों तक कभी पहुंचना कठिन था,वहां अब सड़क, बिजली,आवास,राशन,पेयजल,शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं तेजी से पहुंच रही हैं। सरकार का लक्ष्य विकास की रोशनी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित सभी योजनाओं के भुगतान में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए तथा पंचायत स्तर पर प्रभावी निगरानी व्यवस्था विकसित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। पंचायत स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिक से अधिक परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाए। किसानों और ग्रामीण परिवारों को सौर पंप तथा अन्य सौर ऊर्जा योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

राष्ट्रपति भवन तक पहुँची बस्तर की गौरवगाथा,राष्ट्रपति मुर्मु करेंगी बस्तर पंडुम 2026 के विजेताओं का सम्मान

रायपुर,27 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति,लोकपरंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों,परंपरागत जनजातीय नेतृत्व व्यवस्था के प्रतिनिधियों, पद्मश्री सम्मानित विभूतियों तथा जनप्रतिनिधियों का 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आगामी 30 जुलाई को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार भेंट करेगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बस्तर पंडुम-2026 के विजेता प्रतिभागियों, परगना मांझी, मांझी, चालकी तथा पद्मश्री सम्मानित विभूतियों के सम्मान में विशेष भोज का आयोजन भी किया है। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन का भ्रमण करेगा तथा नई दिल्ली के प्रमुख राष्ट्रीय स्थलों का अवलोकन भी करेगा। यह अवसर बस्तर की जनजातीय संस्कृति,परंपरागत नेतृत्व व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को देश के सर्वोच्च संवैधानिक मंच पर मिल रहे सम्मान का ऐतिहासिक प्रतीक होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार जनजातीय समाज की गौरवशाली विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ उसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रपति भवन में बस्तर के कलाकारों और परंपरागत जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। यह सम्मान बस्तर की संस्कृति,परंपरा और जनजातीय समाज के प्रति पूरे देश के सम्मान का प्रतीक है। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि बस्तर पंडुम-2026 ने यह सिद्ध कर दिया है कि छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति और लोकपरंपराएं राष्ट्रीय ही नहीं,वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाने की क्षमता रखती हैं। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय ज्ञान परंपरा, लोकजीवन,पारंपरिक नेतृत्व व्यवस्था और सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण का सशक्त अभियान बन चुका है। राष्ट्रपति भवन में बस्तर पंडुम के विजेता प्रतिभागियों एवं जनजातीय प्रतिनिधियों का सम्मान पूरे छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक स्वाभिमान का सम्मान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में संस्कृति विभाग द्वारा जनजातीय विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बस्तर पंडुम आज केवल छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय सांस्कृतिक आयोजनों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुका है। लोककलाओं को मंच उपलब्ध कराने,कलाकारों को सम्मान दिलाने, जनजातीय ज्ञान परंपरा का दस्तावेजीकरण करने तथा नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में इस महोत्सव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में पहली बार आयोजित बस्तर पंडुम ने विश्व के सबसे बड़े जनजातीय सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को वैश्विक पहचान दिलाई थी।

छत्तीसगढ़ में 7 आईएफएस अफसरों के तबादले

संजीता गुप्ता को लघु वनोपज संघ का प्रभार, अमरनाथ प्रसाद को राज्य वन विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार

रायपुर,27 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 7 अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक आधार पर जारी आदेश के तहत कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि कुछ को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आदेश के मुताबिक, संजीता गुप्ता को छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ का प्रभारी प्रबंध संचालक बनाया गया है। वहीं एस. वेंकटाचलम को कार्यकारी संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के पद पर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है।

अमरनाथ प्रसाद को वन विकास निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार : अमरनाथ प्रसाद सचिव, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पद पर बने रहेंगे। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इसके अलावा अभिषेक कुमार सिंह को प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख कार्यालय में वन संरक्षक बनाया गया है।

टाइगर रिजर्व में गुरुनाथन और प्रणय मिश्रा को नई जिम्मेदारी : गुरुनाथन एन. को उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व का प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र संचालक नियुक्त किया गया है। वहीं प्रणय मिश्रा को गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व का प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एवं क्षेत्र संचालक तथा प्रोजेक्ट एलीफैंट का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

रमेश जांगड़े बने क्षेत्रीय महाप्रबंधक : रमेश कुमार जांगड़े को छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम में क्षेत्रीय महाप्रबंधक का प्रभारी बनाया गया है।

सौरभ चंद्राकर के खिलाफ दोबारा गिरफ्तारी वारंट जारी

महादेव ऐप के मास्टरमाइंड के प्रत्यर्पण की तैयारी तेज,इस बार ईडी ने जारी कराया वारंट

रायपुर,27 जुलाई 2026। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को भारत लाने की प्रक्रिया में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एजेंसी ने ओमान से उसके प्रत्यर्पण के लिए स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से फिर से ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया है। वारंट जारी होने के बाद प्रत्यर्पण से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज तैयार कर भारत के हाई कमीशन को भेज दिए गए हैं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडे ने बताया कि एजेंसी को सूचना मिली थी कि सौरभ चंद्राकर दुबई में है। इसी आधार पर स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया था और प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक दस्तावेज दुबई भेजे गए थे। बाद में जांच के दौरान यह जानकारी सामने आई कि सौरभ दुबई छोड़कर ओमान पहुंच गया है। इसके बाद ईडी ने रायपुर की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में नया आवेदन पेश किया। कोर्ट ने 16-17 जुलाई में दोबारा ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट जारी किया,ताकि ओमान के माध्यम से प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

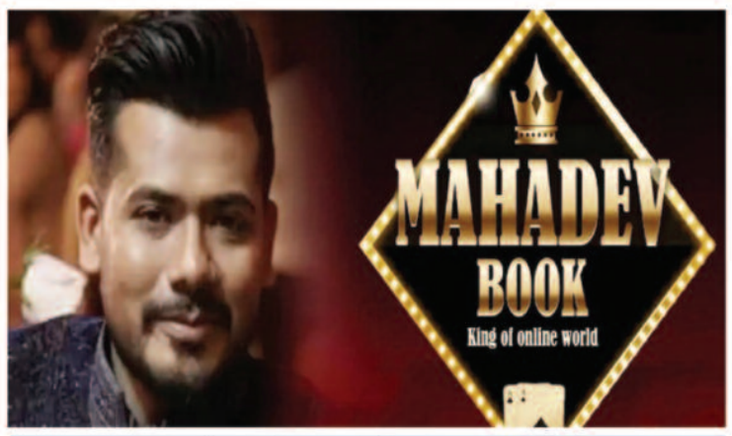

हाई कमीशन भेजे गए दस्तावेज

वकील सौरभ पांडे ने बताया कि कोर्ट से वारंट मिलने के बाद प्रत्यर्पण से संबंधित सभी दस्तावेजों पर आवश्यक न्यायिक एंडोर्समेंट कराए गए। इसके बाद सारे दस्तावेज भारत के हाई कमीशन को भेज दिए गए। अब मामला ओमान में संबंधित अधिकारियों और भारतीय एजेंसियों के समन्वय से आगे बढ़ रहा है। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि सौरभ चंद्राकर को भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। अब प्रत्यर्पण की अगली कार्रवाई दोनों देशों के बीच तय प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

क्या होता है ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट?

ओपन-एंडेड गिरफ्तारी वारंट ऐसा वारंट होता है, जिसकी कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं होती। यह तब तक प्रभावी रहता है, जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो जाती या संबंधित अदालत इसे वापस नहीं लेती। विदेश में फरार आरोपियों के मामलों में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाए रखने के लिए ऐसे वारंट का इस्तेमाल किया जाता है।

अब तक 4336 करोड़ की संपत्तियां अटैच

ईडी ने इस मामले में अब तक 175 से ज्यादा ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन किए गए। 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 74 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में 5 प्रॉसिक्यूशन शिकायतें दाखिल की गई हैं। एजेंसी के मुताबिक अब तक इस मामले में कुल 4336 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां अटैच, सीज या फ्रीज की जा चुकी हैं।

एआई वीडियो विवाद में महिला आयोग सख्त

कांग्रेस के 2 नेताओं पर एफआईआर के निर्देश,3 दिन में मांगी रिपोर्ट

रायपुर,27 जुलाई 2026। सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट और एआईसे बनाए गए फोटो-वीडियो के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने सख्ती दिखाते हुए कांग्रेस के 2 नेताओं पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। आयोग अध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने पुलिस से 3 दिन के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने फेसबुक पर महिलाओं की छवि और सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आरोप है कि आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ एआईतकनीक से तैयार फोटो और वीडियो भी शेयर किए गए। महिला आयोग ने इसे 'महिलाओं की गरिमा से जुड़ा गंभीर मामला' मानते हुए तत्काल जांच और कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

किन दो कांग्रेस नेताओं पर लगे आरोप?

1. संजय बघेल - भाटापारा शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महामंत्री एवं पूर्व पार्षद
2. सुरेन्द्र वर्मा - बिलासपुर कांग्रेस पदाधिकारी

आरोप है कि दोनों के फेसबुक अकाउंट से महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां, फोटो और वीडियो पोस्ट किए गए।

एआईकंटेंट की भी होगी अलग से जांच

इस मामले में महिला आयोग ने एआई के गलत इस्तेमाल को गंभीरता से लिया है। आयोग ने कहा है कि अगर आपत्तिजनक फोटो-वीडियो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बनाए गए हैं तो उनकी अलग से जांच की जाएगी। पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महिला आयोग ने साफ किया कि सिर्फ पोस्ट करने वाले ही नहीं, बल्कि कंटेंट बनाने और उसे आगे बढ़ाने वाले सभी लोगों की भूमिका की जांच होगी। आयोग ने बलौदाबाजार और बिलासपुर के पुलिस अधीक्षकों से भी चर्चा की है।

11.38 करोड़ का लोन घोटाला..सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर

इसमें केपेक्स-कंपनी की डायरेक्टर का नाम,कैश क्रेडिट से दूसरे लोन चुकाने का आरोप

बलौदाबाजार,27 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में राजकुमार सराफ के मकान में कार्रवाई हुई। शुरुआत में इसे ईडी की रेड से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन एफआईआर कॉपी के अनुसार यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से की गई है। इसके अलावा आईटी ने भी मामले में कार्रवाई की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने करीब 11.38 करोड़ के बैंक लोन घोटाले के मामले में धमतरी केपेक्स प्राइवेट लिमिटेड,उसके डायरेक्टरों, गारंटर,अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि आरोपियों ने आपसी मिलीभगत से बैंक को धोखा देकर लोन की राशि का गलत इस्तेमाल किया। इसके साथ ही बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। साफ शब्दों में कहे तो सभी पर कैश क्रेडिट से पैकिंग क्रेडिट चुकाने का आरोप है। धमतरी केपेक्स प्राइवेट लिमिटेड बॉक्साइट की बिक्री और निर्यात का कारोबार करती थी। कंपनी से जुड़ी केएसआर इंफ्रा और केपेक्स 2 एंटरप्राइजेज नाम की दो अन्य फर्में भी संचालित की जा रही थीं। इसी कारोबार के लिए कंपनी ने बैंक से लोन लिया था।

7 मई को बैंक ने की शिकायत

सीबीआई की एफआईआर के अनुसार,यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रीजनल ऑफिस रायपुर के डिप्टी जनरल मैनेजर और रीजनल हेड रणधीर कुमार ने 7 मई 2026 को शिकायत दी थी। शिकायत में कहा गया कि कंपनी और उसके जिम्मेदार लोगों ने बैंक से मिली क्रेडिट सुविधा का दुरुपयोग कर धोखाधड़ी की।

15 करोड़ की एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट सुविधा ली...

जांच में सामने आया कि 19 अप्रैल 2023 को कंपनी को 15 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट सुविधा मंजूर हुई थी। इसमें 5 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट सीमा और 7 .50 करोड़ रुपए की लेटर ऑफ क्रेडिट सीमा शामिल थी।

सिस्टर कंसर्न के जरिए रकम घुमाने का आरोप

सीबीआई के अनुसार,कंपनी ने लोन की रकम को सीधे कारोबार में लगाने के बजाय अपनी सहयोगी फर्मों भारत मल्टी ट्रेड, क्रिस एंटरप्राइजेज और राधे कृष्णा एंटरप्राइजेज के खातों में ट्रांसफर किया। जांच में यह भी सामने आया कि भारत मल्टी ट्रेड के मालिक संतोष कुमार रमानी, कंपनी की सहयोगी फर्म केपेक्स 2 एंटरप्राइजेज से जुड़े हैं। क्रिस एंटरप्राइजेज के मालिक कृतार्थ सोनी, कंपनी के गारंटर कुशल सोनी के भाई हैं। सीबीआई का आरोप है कि कंपनी ने कैश क्रेडिट खाते से निकाली गई रकम को अलग-अलग फर्मों के जरिए घुमाकर उसी दिन पैकिंग क्रेडिट खाते में जमा कराया। इससे ऐसा दिखाया गया कि पैकिंग क्रेडिट का भुगतान किया गया है।

अनुज शर्मा की सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर हाईकोर्ट सख्त

मॉर्फ फोटो और अश्लील पोस्ट हटाने के आदेश,विधायक बोले...छवि खराब करने की साजिश...

बिलासपुर,27 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धरसींवां विधायक और छालीवुड अभिनेता अनुज शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रही कथित ट्रोलिंग को लेकर सख्ती दिखाई है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने पहली नजर में मामला गंभीर मानते हुए अनुज शर्मा और उनके परिवार की मॉर्फ फोटो, एडिटेड वीडियो, अश्लील कमेंट,कैरिकेचर और अन्य आपत्तिजनक पोस्ट तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने यह कंटेंट पोस्ट करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स और संबंधित प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। याचिका में विधायक अनुज शर्मा ने बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (पहले ट्विटर) और यूट्यूब पर फर्जी और बेनाम अकाउंट्स से उन्हें निशाना बनाया गया। उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर मॉर्फ वीडियो, एडिटेड फोटो, अश्लील कैरिकेचर और आपत्तिजनक कमेंट वायरल किए गए। उनकी मूवी और गानों के हिस्सों को भी एडिट कर गलत तरीके से फैलाया गया, ताकि उनकी सामाजिक और सार्वजनिक छवि खराब हो। याचिका में कहा गया है कि यह सिर्फ राजनीतिक आलोचना का मामला नहीं, बल्कि सोची-समझी साजिश के तहत उनकी छवि और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। सुनवाई के दौरान अनुज शर्मा की ओर से कहा गया कि किसी व्यक्ति की फोटो, आवाज, पहचान या व्यक्तित्व का उसकी अनुमति के बिना इस्तेमाल करना उसके व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) का उल्लंघन है। यह संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले सम्मान और निजता के अधिकार का भी उल्लंघन है। हाईकोर्ट को बताया गया कि अनुज शर्मा धरसींवां के विधायक होने के साथ पद्मश्री सम्मानित कलाकार भी हैं। उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज, क्लिक और राजनीतिक फायदा लेने के लिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मामले से जुड़े लोगों को निर्देश दिया कि अनुज शर्मा और उनके परिवार से जुड़ी सभी आपत्तिजनक पोस्ट, मॉर्फ वीडियो, एडिटेड फोटो और कैरिकेचर तुरंत हटाए जाएं।

थाने पहुंचे सीएम साय के प्रमुख सचिव,फेक एफबी आईडी बनाकर पैसे मांग रहा अपराधी

रायपुर,27 जुलाई 2026। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म अब वसूली का नया जरिया बन गए हैं। इसके लिए शातिर ठग फेक आईडी का सहारा ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह से जुड़ा हुआ आया है, जिसमें शातिर फेसबुक में उनकी फेक आईडी बनाकर परिचितों से पैसे मांग रहा है। जानकारी के अनुसार, शातिर ठग ने आईएएस सुबोध सिंह का फेसबुक पर आज ही एक फेक आईडी बना डाला। न केवल आईडी बना लिया, बल्कि दो घंटे के भीतर 58 दोस्त भी बना डाले।

यह सब शातिर ने परिचितों से पैसे मांगने के लिए किया था। फेक आईडी के जरिए पैसे मांगने की जानकारी मिलते ही आईएएस सुबोध सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)